कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

lnL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDl : +91(11) 23387887

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक - प्रभात झा

विषय-सूची

भाजयुमो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता यात्रा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की चीन सद्भावना यात्रा
एक रिपोर्ट..... 6
कर्नाटक : राज्यपाल को वापस बुलाओ..... 11

राष्ट्रीय एकता यात्रा
एक रिपोर्ट..... 15
साक्षात्कार : श्री अनुराग ठाकुर..... 19

लेख
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार को लताड़ना शर्म की बात
ykyÑ".k vkMok.kh..... 7
कश्मीर में तिरंगा फहराना एक अपराध?
v- p- of'k"B..... 21

रैली
जम्मू: एकता संकल्प रैली..... 12
मुंबई : महासंग्राम रैली..... 13
ओडिशा : भ्रष्टाचार विरोधी रैली..... 14

राज्यों से
fnYyh % प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन..... 26
eè; inz'k % संभागीय पदाधिकारी बैठक..... 27
mÙkjk[kM % नव वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम..... 27
xqtjkr % 'वाइब्रेंट गुजरात' सम्मेलन..... 28
egkjk"Vª % मुस्लिम महिला विकास सम्मेलन..... 29
mÙkj çn'k % विकास व स्वच्छ प्रशासन ही एजेंडा..... 30
dkjy % राज्य रक्षा पदयात्रा..... 30

कमल संदेश के सुधी पाठकों को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं!

वर दे, वीणावादिनि वर दे!
प्रिय स्वतंत्र-रव अमृत-मंत्र नव
भारत में भर दे!

काट अंध-उर के बंधन-स्तर
बहा जननि, ज्योतिर्मय निर्झर;
कलुष-भेद-तम हर प्रकाश भर
जगमग जग कर दे!

नव गति, नव लय, ताल-छंद नव
नवल कंठ, नव जलद-मन्द्ररव;
नव नभ के नव विहग-वृंद को
नव पर, नव स्वर दे !

वर दे, वीणावादिनि वर दे।

-सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

व्यंग्य चित्र

संपादक के नाम पत्र...

आदरणीय संपादक महोदय,

कमल संदेश (जनवरी 16–31) पढ़ा। गुवाहाटी (असम) में संपन्न भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण का पूरा पाठ पढ़ने का मौका मिला। साथ ही बैठक में पारित किए गए राजनीतिक एवं उत्तर–पूर्व राज्यों पर केन्द्रित प्रस्ताव भी। श्री गडकरी ने अपने सारगर्भित एवं ओजस्वी भाषण में महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेसनीत यूपीए सरकार पर उचित ही प्रहार किया है। आज महंगाई और भ्रष्टाचार ने देशवासियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। यूपीए सरकार के मंत्रीगण जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले को अंजाम दे रहे हैं और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी तथा प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जिस तरह से मौन हैं, इससे वे भी स्वतः कटघरे में खड़े हो जाते हैं। देश में चारों ओर अराजकता व्याप्त है। आतंकवाद पर केन्द्र सरकार का रवैया लचीला है। नक्सलवाद भी देश भर में अपने पैर पसार रहा है। सामाजिक विषमता प्रबल है। गरीबी और अमीरी के बीच खाई बढ़ती जा रही है। बेलगाम महंगाई के चलते आम आदमी को दो वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल हो गया है। यूपीए सरकार के प्रति जनता में बेहद आक्रोश व्याप्त है। भाजपा को चाहिए कि वह जन–पीड़ा से मुक्ति के लिए आंदोलन चलाएं।

– संजय कुमार
पटना (बिहार)

हमें लिखें..

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी–66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003
ई-मेल:
kamalsandesh@yahoo.co.in

सम्पादकीय

राष्ट्रीय एकता यात्रा से हुआ राष्ट्रवादी चेतना का संचार

जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह कहना कि हम 26 जनवरी 2011 को श्रीनगर स्थित लालचौक पर भाजयुमो को तिरंगा नहीं फहराने देंगे, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा करने से घाटी में अशांति होगी। क्या ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति को, जो भारत में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने से रोके और यह कहे कि घाटी में अशांति होगी, को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद पर एक मिनट भी रहने देना चाहिए? ऐसे असहाय मुख्यमंत्री से भारत की संसद में सर्वसम्मति से पारित वह प्रस्ताव कि ''जम्मू–कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और हमें पाक अधिकृत कश्मीर को भी अपने कब्जे में लेना है'' कभी पूरा हो सकता है?

क्या ऐसे मुख्यमंत्री को भारत की एकता, अखंडता और उसकी सम्प्रभुता के लिए प्रतिबद्ध माना जाए? क्या हो गया है भारत की कांग्रेस नीत यूपीए सरकार को? क्या वह भी असहाय और लाचार है? अभी तक जो केन्द्र की नीति जम्मू–कश्मीर के बारे में है उससे यह बात तो साफ हो जाती है कि कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार को जम्मू–कश्मीर से अधिक अपनी कुर्सी की चिंता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उमर अब्दुल्ला अभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नहीं होते। भ्रष्टाचार में आंकठ डूबी यूपीए सरकार लाचार हो चुकी है। लगता ही नहीं कि देश में कोई सरकार है। आजादी के 63 वर्ष में देश ने ऐसा दौर कभी नहीं देखा।

लगता है कि कांग्रेसनीत यूपीए सरकार और जम्मू–कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार यह सोच रही है कि भाजयुमो का लालचौक पर तिरंगा फहराने का निर्णय राजनैतिक स्टंट है। यह सोच और समझ ही पूरी तौर पर गलत है। भाजयुमो देश की जनता को कश्मीर की बदतर स्थिति और उस पर मंडरा रहे खतरे की घंटी से देश को जगाना चाहता है और वह अपने इस मिशन में निरंतर सफल हो रहा है। भाजयुमो की राष्ट्रीय एकता यात्रा मोर्चा अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में अनेक राज्यों से लगभग तीन हजार से भी अधिक किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जम्मू–कश्मीर के लालचौक पर पहुंचेगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जम्मू–कश्मीर का मुद्दा राजनैतिक नहीं, राष्ट्रीय है और किसी दल विशेष का नहीं बल्कि देश का है। चाहिए तो यह था कि केन्द्र शासित कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला मिलकर भाजयुमो के इस साहसिक निर्णय का हार्दिक स्वागत करते और उनकी राष्ट्रीय एकता यात्रा की अगवानी करते। काश! ऐसा होता।

भारत की विडम्बना यही है कि हम राष्ट्रीय मुद्दों पर भी एक नहीं हो पाते और अपनी कुर्सी बचाने के लिए राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को भी दांव पर लगा देते हैं। इससे अधिक शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? भाजयुमो की राष्ट्रीय एकता यात्रा को लालचौक तक शायद सरकार न जाने दे। हो सकता है कि सत्याग्रहियों को रास्ते में ही गिरफ्तार कर ले। पर इससे केन्द्र की कांग्रेस–नीत यूपीए और जम्मू–कश्मीर दोनों ही सरकारों के सिर शर्म से झुक जायेंगे। क्या लालचौक भारत का हिस्सा नहीं है? अगर है तो फिर वहां तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाएगा? क्या वहां झंडा नहीं फहराने देना, इस बात का सबूत नहीं है कि आंतकवादियों और अलगाववादियों के सामने कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस घुटने टेक चुके हैं? भाजयुमो की राष्ट्रीय एकता यात्रा तब भी सफल होगी जब वे लालचौक पर तिरंगा फहरायेंगे और उन्हें वहां तिरंगा नहीं फहराने दिया गया तो भी उनकी यात्रा सफल हो जाएगी। भाजयुमो देश के सामने कश्मीर की असलियत को लाना चाहता था और वह पूरी तौर पर आ गई। भाजयुमो को बधाई, इसलिए कि उन्होंने एक ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दे को राष्ट्र के सामने लाने के लिए सार्थक जनजागरण अभियान चलाया।

पूरे देश को जम्मू–कश्मीर के मसले पर खड़ा होना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की नासमझी से हमारा संकटग्रस्त जम्मू–कश्मीर और अधिक खतरे में पड़ जाए। हमें सभी को जगाना होगा और पूरे राष्ट्र को जगाना होगा।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की चीन सद्भावना यात्रा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के आमंत्रण पर अपनी पत्नी श्रीमती कंचन गडकरी एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के शिष्टमण्डल के साथ 19 जनवरी को सद्भावना यात्रा पर रवाना हो गए। उनके शिष्टमण्डल में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री थावरचन्द गहलोत एवं श्री विजय गोयल, संयुक्त संगठन महासचिव श्री सौदान सिंह, सचिव लक्ष्मण कोवा और श्रीमती आरती मेहरा, उनके राजनीतिक एसोसिएट श्री विनय सहस्रबुद्धे तथा पार्टी के विदेश कार्य प्रकोष्ठ श्री विजय जौली शामिल है।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 'किसी भी भाजपा अध्यक्ष की इस प्रथम यात्रा' को अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टि से देखती है क्योंकि इससे पार्टी स्तर पर सद्भावना बढ़ेगी और दोनों पक्ष एक दूसरे के हितों को समझने में आदर्श सिद्ध होंगे। भाजपा का यह शिष्टमण्डल बीजिंग, शंघाई और गुआंगाजू जाएगा और वहां आपसी हितों के मुद्दों पर बात करेगा।

20 तारीख को बीजिंग पहुंचने पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका भव्य एवं हार्दिक अभिनंदन किया।

श्री गडकरी ने कहा कि ''चीन पहुंच कर चीनी नेताओं से बातचीत करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। चीन हमारा पड़ोसी देश है और हम चीन के साथ 3500 कि.मी. की सीमा में सांझेदारी करते हैं। हम लोगों के 1600 वर्ष पुराने सांस्कृतिक सम्बंध है जो निरंतर बढ़ते रहे हैं।

उन्होंने 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा का स्मरण कराते हुए कहा कि उस समय दोनों देशों ने सीमा मुद्दे पर भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों के विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत पर सहमति जताई थी।

श्री नितिन गडकरी ने चीन के नेताओं से बहुत स्पष्ट रूप से बात करते हुए सर्वप्रथम पाकिस्तान–प्रायोजित आतंकवाद पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में बीजिंग विकास परियोजना पर भारत के लोगों को अत्यंत आक्रोश है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान आधारित 'जमातुद दवाह' जैसे संगठनों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा काली सूची में डाले जाने पर आपत्ति करने के बीजिंग के प्रयासों से भारत में रोष व्याप्त है जिससे भाजपा द्वारा चीन के लोगों के साथ सम्पर्क करने के मामले में हमारे प्रयासों पर विपरीत असर पड़ रहा है, जबकि यह संगठन पहले ही प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन है।

श्री गडकरी ने कहा कि चीन का पाकिस्तान पर गहरा प्रभाव है और भाजपा उम्मीद करती है कि वह इन मुद्दों पर इस्लामाबाद पर अपनी धरती से आतंकवादी गतिविधियां रोकने के लिए कहेगा।

चीन के नेताओं ने भी आतंकवाद पर अपनी सहमति जताई और कहा कि बीजिंग भाजपा अध्यक्ष द्वारा उठाए गए इन सभी मुद्दों के महत्व को समझता है।

भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि

हमारी पार्टी अरूणाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर के लोगों के लिए 'नत्थी वीजा' के मुद्दे पर भी कड़ी आपत्ति जताना चाहती है और आशा करती है कि इसे जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा।

अन्य मुद्दों का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण दोनों देशों के सम्बंधों के बीच बाधा आती है, उनमें चीन द्वारा पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिएक्टरों की सप्लाई भी शामिल है। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र की नदी के पानी को दूसरी दिशा में किए जाने की योजना से भी

शेष पृष्ठ 10 पर

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार को लताड़ना शर्म की बात

✍ ykyÑ".k vkMok.kh

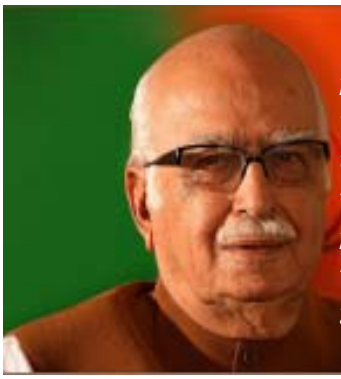

सभी मूल्यांकनों की कसौटी पर कसे तो मनमोहन सिंह सरकार अपने साढ़े 6 वर्ष के कार्यकाल में सर्वाधिक गंभीर संकट से गुजर रही है। स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और मुंबई के रक्षा मंत्रालय भूमि सम्बन्धी घोटाले एक साथ इस रूप में सामने आए हैं जिससे आम आदमी को यह महसूस होने लगा है कि आज सरकार में अनेक मंत्री न केवल मक्कारी से धन बना रहे हैं अपितु वे देश को निर्लज्जता से लूट रहे हैं।

सभी मूल्यांकनों की कसौटी पर कसे तो मनमोहन सिंह सरकार अपने साढ़े 6 वर्ष के कार्यकाल में सर्वाधिक गंभीर संकट से गुजर रही है। स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और मुंबई के रक्षा मंत्रालय भूमि सम्बन्धी घोटाले एक साथ इस रूप में सामने आए हैं जिससे आम आदमी को यह महसूस होने लगा है कि आज सरकार में अनेक मंत्री न केवल मक्कारी से धन बना रहे हैं अपितु वे देश को निर्लज्जता से लूट रहे हैं।

ज्यादा चिन्ताजनक यह है कि यह संकट सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं अपितु देश के लिए भी है, भ्रष्टाचार और मुद्रास्फीति के वर्तमान स्तर ने राष्ट्र के सामूहिक आत्मविश्वास को खोखला कर दिया है।

ऐसी स्थिति सदैव मुझे 1975–77 में भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख पैदा हुए गंभीर संकट का स्मरण करा देती है। तब भी राष्ट्र ने सभी आशाएं खो दी थी कि क्या 1975 से पूर्व का स्वतंत्रता का माहौल फिर कभी वापस लौट सकेगा।

भला हो राष्ट्र के मूड को समझने में सरकार के समूचे गलत आकलन का, जिसके चलते चुनावों की घोषणा हो गई। मतदाताओं ने सभी को चकित कर दिया रू उन्होंने कांग्रेस पार्टी की इतनी पिटाई की कि वह फिर कभी भी आपातकाल, अनुच्छेद 352 (युद्ध के अपवाद को छोड़) लागू करने की सोचेगी भी नहीं।

लगभग सभी उच्च न्यायालयों ने भारत सरकार की इस दलील को रद्द कर दिया कि जब आपातकाल लागू हो तो भारतीय सविंधान के तहत किसी भी बंदी को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का भी अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालयों को कहा कि किसी भी समय पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का अधिकार निलम्बित नहीं किया जा सकता। इस भूमिका को अपनाने के फलस्वरूप उच्च न्यायालयों ने 19 न्यायाधीशों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित कर दण्डित किया गया।

हालांकि मुख्य न्यायाधीश ए.एन. रे (उनकी नियुक्ति तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों सर्वश्री हेगड़े, सेलट और ग्रोवर की वरिष्ठता का उल्लंघन करने के बाद हुई थी) की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय एटार्नी जनरल नीरेन डे की इस दलील से सहमत था कि यदि किसी बंदी को किसी सरकारी काम से गोली मार दी जाए तो भी उसके परिवारवालों को न्यायालय के द्वार खटखटाने का अधिकार नहीं है। न्यायाधीश एच. आर. खन्ना ने इस निर्णय के विरुद्ध अपनी सशक्त असहमति दर्ज की और न्यायिक इतिहास में चिरस्थायी स्थान अर्जित किया है।

कुछ सप्ताह पहले के अपने ब्लॉग में मैंने राम जेठमलानी, सुभाष कश्यप और के.पी.एस. गिल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका कि विदेशों के – टैक्स हेवन्स में जमा भारतीय धन को भारत वापस लाने हेतु सरकार को बाध्य किया जाए – का उल्लेख किया था।

15 जनवरी को सुबह समाचारपत्रों में यह समाचार पढ़कर लाखों पाठक अवश्य ही प्रफुल्लित हुए होंगे कि एक दिन पूर्व न्यायालय ने सोलिसीटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम को उस समय बुरी तरह से लताड़ा जब उन्होंने यह बताया कि सरकार को जर्मन सरकार से लीसटेनस्टीन बैंक में जमा सभी भारतीय नागरिकों के धन के बारे में पूरी

जानकारी मिली है लेकिन भारत सरकार इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहती।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी और एस.एस. निर्झर की पीठ ने सुब्रमण्यम से पूछा "जिन लोगों ने विदेशी बैंकों में धन जमा किया है उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक न करने के पीछे कौन सा विशेषाधिकार है?" न्यायालय ने आगे कहा कि वे चाहेंगे कि पुणे के व्यवसायी हसन अली खान जिसके विरूद्ध विदेशी बैंको में कथित काला धन जमा कराने की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने की थी, को भी याचिका में एक पार्टी के रूप में शामिल किया जाए। न्यायालय की टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में, सोलिसीटर जनरल ने कहा कि वे सरकार से निर्देश लेंगे।

गत् सप्ताह इस समूचे मुद्दे पर विचार करने के लिए एन.डी.ए. की एक विशेष बैठक हुई। संसद में एन.डी.ए. के सभी दलों के सदन के नेताओं ने भाग लिया और प्रधानमंत्री को एक कड़ा पत्र तैयार किया। इस पत्र के तीन पैराग्राफ निम्नलिखित हैं: "हमारी आशंका है कि इस मोर्चे पर यूपीए सरकार द्वारा सक्रियता न दिखाने के पीछे उसे स्वयं अपने फंसने का डर है। आखिरकार, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'फूड फॉर ऑयल' घोटाले की जांच हेतु गठित वोल्कर रिपोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को एक लाभार्थी के रूप में नामित किया है। हमारी जांच एजेंसियों और राजस्व एजेंसियों की जांच में यह साफ सिद्ध हुआ है जो कि ITAT के आदेश में भी परिलक्षित होता है कि बोफोर्स घूस काण्ड में दलाली लेने वालों मे

ओतावियो क्वात्रोची ने ए.ई. सर्विसेज और कोल बार इन्वेस्टमेंट जैसी कम्पनियों की आड़ में घूस ली है। ओतावियो क्वात्रोची और उनकी पत्नी मारिया के कांग्रेस पार्टी के परिवार विशेष से सम्बन्ध सर्वज्ञात हैं और उन पर कोई विवाद नहीं है।

एक स्विस पत्रिका Sehweizer Illustrirte* के 19 नवम्बर, 1991 के अंक में प्रकाशित एक खोजपरक समाचार में तीसरी दुनिया के 14 वैश्विक नेताओं के नाम दिए गए है। जिनके स्विट्जरलैण्ड में खाते हैं। भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम भी इसमें शामिल है। रिपोर्ट का आज तक खण्डन नहीं किया गया। डा0 येवजेनिया एलबट्स की पुस्तक "The state within a state - The KGB hold on Russia in past and future" में चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन किए गए हैं कि भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को रूस के व्यावसायिक सौदों के बदले में लाभ मिले हैं।

ओतावियो क्वात्रोची ने ए.ई. सर्विसेज और कोल बार इन्वेस्टमेंट जैसी कम्पनियों की आड़ में घूस ली है। ओतावियो क्वात्रोची और उनकी पत्नी मारिया के कांग्रेस पार्टी के परिवार विशेष से सम्बन्ध सर्वज्ञात हैं और उन पर कोई विवाद नहीं है।

ये शोधपरक समाचार हैं जो लेखों या पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुए हैं। जिनके विरूद्ध जांच की गई है उन्होंने औपचारिक रूप से न तो इसका खण्डन किया है और न ही उन्होंने ऐसे संदेह पैदा करने वाले प्रकाशनों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की है। यह सरकार के लिए महत्वपूर्ण है कि वह सुनिश्चित करे कि पूर्व प्रधानमंत्री सहित भारत के अतीत एवं वर्तमान नेताओं के नाम पर कलंक न लगे। अतः या तो इन आरोपों को जोरदार ढंग से खण्डन करना चाहिए या इनकी जांच होनी चाहिए।"

वैश्विक अर्थव्यवस्था में शुचिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक स्वैच्छिक संगठन ग्लोबल फाइनेंशियल इंटिग्रिटी (Global Financial Integrity) अच्छा काम कर रहा है। पिछले महीने ग्लोबल फाइनेंशियल इंटिग्रिटी द्वारा जारी एक सारगर्भित रिपोर्ट भारत के बारे में कुछ यह कहती है:

"1948 से 2008 तक भारत ने अवैध वित्तीय प्रवाह (गैरकानूनी पूंजी पलायन) के चलते कुल 213 मिलियन डालर की राशि गंवा दी है। यह अवैध वित्तीय प्रवाह सामान्यतया भ्रष्टाचार, घूस और दलाली तथा आपराधिक गतिविधियों से जन्मता है।" अवैध वित्तीय प्रवाह अवैध रूप से कमाए गए, स्थानांतरित या उपयोग में लाए गए देश से बाहर भेजे गए धन से जुड़ता है। इसमें सामान्यतया "भ्रष्टाचार, सौदे के बदले सामान, आपराधिक गतिविधियों जैसी गैर–कानूनी गतिविधियों से कमाए गए धन का स्थानांतरण और देश के कर से बचाने के लिए सम्पत्ति को संरक्षण देना शामिल है।"

रिपोर्ट आगे जोड़ती है "भारत की वर्तमान कुल अवैध वित्तीय प्रवाह की वर्तमान कीमत कम से कम 462 बिलियन डालर है। यह अल्पावधि अमेरिका ट्रेजरी बिल की दरों पर सम्पत्ति पर लाभ के दरों की बराबर पर आधारित है।" देश आशा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को इसकी तार्किक परिणति तक ले जाएगा। 462 बिलियन डालर बहुत बड़ी राशि है। भारतीय रूपयों में यह राशि 20 लाख 85 हजार करोड़ रूपये बैठती है जो भारतीय परिस्थितियों का अद्भुत कायाकल्प कर सकती है। इस सारी दौलत को वापस लाने के लिए सरकार को बाध्यकर सर्वोच्च न्यायालय भारत की जनता की सदैव के लिए कृतज्ञता हासिल कर सकता है। ■

कालेधन पर प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे है : शान्ता कुमार

Hkkरतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्य सभा सदस्य श्री शान्ता कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके मंत्रिमण्डल के सदस्य विदेशों में काले धन के मामले पर देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है यह अन्यत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विदेशों के काले धन के सवाल पर भारत सरकार सही स्थिति देश को नहीं बता रही है। सम्भवतः यह किसी राजनैतिक दबाव के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सही स्थिति यह है कि स्विस सरकार धन लौटाना चाहती है और उसने भारत सरकार को अवगत करवा दिया है लेकिन भारत सरकार इस संबंध में आवश्यक शर्तें और औपचारिकताएं पूरा नहीं कर पा रही है।

भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने वक्तव्य में इस काले धन को टैक्स–चोरी का मामला कहा है। वस्तुतः यह केवल टैक्स चोरी का ही मामला नहीं है यह काला धन गैर कानूनी तरीके से और भ्रष्टाचार से अर्जित किया हुआ धन है जो आपराधिक मामले की श्रेणी में आता हैं।

21 जनवरी को प्रैस को जारी एक विज्ञप्ति में श्री शान्ता कुमार ने कहा कि गत वर्ष भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में उन्हें यू0एन0 जरनल असेम्बली में भाग लेने का अवसर मिला था जहां भ्रष्टाचार और विदेशों से प्रवाहित काले धन के मामले पर भी चर्चा हुई थी। उन्होंने भी इस चर्चा में भाग लिया था। 20 अक्तूबर को उनके सामने स्विस प्रतिनिधि मिथायस बैचमैन ने अपने वक्तव्य में कहा था कि स्विस सरकार इस धन को चोरी की सम्पत्ति मानती है और इसे सम्बन्धित देश को वापिस लौटाने के लिए कृत संकल्प है। स्विस प्रतिनिधि ने यह भी घोषणा की थी कि स्विस सरकार ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध सयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव (यूनाइटिट नैशनल कन्वैन्शन अगेंस्ट क्रप्शन) पर हस्ताक्षर कर उसे पुष्टि भी कर दिया था। इतना ही नहीं स्विस संसद ने एक कानून भी पारित किया है ताकि संबन्धित देशों को अवैध धन लौटाया जा सके। स्विस प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया था कि यह धन वापिस लेने की पहल सम्बन्धित देश की राजनैतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। स्विस प्रतिनिधि ने यह भी रहस्योद्घाटन किया था कि उनकी सरकार ने बहुत से देशों का धन लौटाना भी शुरू कर दिया है।

श्री शान्ता कुमार ने कहा भारत सरकार इस धन को वापिस स्वदेश लाने के लिए वह पहल भी नहीं कर रही है। उन्होने कहा कि समस्त विश्व भ्रष्टाचार से चिन्तित है और इस संबंध में सयुंक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने दो वर्षों की लम्बी चर्चा के बाद भ्रष्टाचार के विरूद्ध एवं ऐतिहासिक प्रस्ताव (यूनाइटिट नेशन्स कन्वैन्शन अगेंस्ट कप्शन) पारित किया था। इस प्रस्ताव की धारा 51 के अनुसार इस प्रस्ताव का बुनियादी उददेश्य विभिन्न देशों का धन लौटाने में सहयोग करना है। धारा 52 के अनुसार इस प्रकार के लोगों की पहचान करने में सहयोग भी दिया जाएगा। इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करने वाले 148 देश थे जिन में से 140 देशों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये। भारत सरकार ने हस्ताक्षर करने में ही दो वर्ष लगा दिये और प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के निर्धारित अन्तिम दिन 9 दिसम्बर 2005 को इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये। परन्तु पांच वर्ष बीत जाने के बाद आज तक भारत सरकार इस प्रस्ताव को पुष्टि नहीं कर पाई है। इस प्रस्ताव के अनुसार जब तक कोई देश प्रस्ताव की पुष्टि नहीं करता तब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। विदेशी बैंकों से धन

वापिस लेने के लिए एक मात्र अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी साधन राष्ट्र संघ का यह प्रस्ताव है। इसी के अन्तर्गत विश्व के विभिन्न देश अपना धन लेने की कोशिश कर रहे है। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि ही नहीं की है। इसलिए स्विट्जरलैण्ड से सहयोग के बाद भी भारत इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकता।

भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने वक्तव्य में इस काले धन को टैक्स–चोरी का मामला कहा है। वस्तुतः यह केवल टैक्स चोरी का ही मामला नहीं है यह काला धन गैर कानूनी तरीके से और भ्रष्टाचार से अर्जित किया हुआ धन है जो आपराधिक मामले की श्रेणी में आता हैं। उन्होंने कहा कि पुणे के घोड़ा फार्म मालिक हसन अली के मुम्बई एवं पुणे ठिकानों पर छापों के बाद विदेशी बैंकों में एक लाख करोड़ रूपये का पता चला। आयकर विभाग ने उसे 40 हजार करोड़ रूपये टैक्स अदा करने का नोटिस दिया। परन्तु उसने एक लाख करोड़ रूपये कहां से लेकर विदेशों में जमा करवाया इस बारे में पूछा ही नहीं गया। इस सारे मामले को केवल टैक्स चोरी कह कर सरकार ने पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की। इन्हीं छापों के दौरान हसन अली के दस स्विस बैंकों खातों का पता चला था। हसन अली का मामला महाराष्ट्र की विधान सभा में भी उठा था जहां चर्चा के दौरान बड़े राजनीतिज्ञों की सलिप्तता का भी खुलासा हुआ था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने यह मामला दबा दिया। दुर्भाग्य से हसन अली के स्विस बैंक के खाते की जानकारी लेने मे भी भारत सरकार असफल रही है।

उन्होंने कहा कि केवल स्विस बैंकों में भारत 70 लाख करोड़ जमा है। विश्व की एक अधिकृत संस्था ग्लोबल फाइनेंश्यल इन्टेग्रिटी ने नई रिपोर्ट के अनुसार 1947 से आज तक भारत से कुल लगभग 2 हजार लाख करोड़ रूपया इस प्रकार लूटा जा चुका है। यह विश्व इतिहास की सबसे बड़ी लूट है। शान्ता कुमार ने कहा कि स्विस बैंक से काले धन को स्वदेश वापिस लाने की कार्यवाही भारत सरकार प्राथमिकता के आधार पर करें क्योंकि हो सकता है बिलम्ब से यह धन राशि "टैक्स–स्वर्ग" देशों के बैंकों से खाताधारी निकाल का खुर्दबुर्द न कर दें। ■

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको निरन्तर मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

–सम्पादक

पृष्ठ 6 का शेष

भारत आशंकित है।

श्री गडकरी ने यह भी कहा कि जम्मू और काश्मीर की स्थिति अत्यंत प्रज्जवलनशील है क्योंकि यहीं पर हमारे चिंतक डॉ. श्यामप्रसाद मुकर्जी ने अपना बलिदान दिया था ताकि हमारे देश की एकता और अखंडता की भावना बनी रहे और यह भी कि हम निरंतर मानते हैं कि पाक–अधिकृत काश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है जिसके लिए हम कोई भी कुर्बानी करने को तैयार हैं।

श्री गडकरी ने यह भी कहा कि चीन ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र का 38,000 किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है तथा कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा एक और 5000 कि.मी. क्षेत्र चीन का सौंपा हुआ है, जो अत्यंत चिंता का विषय है।

श्री गडकरी ने यह भी चीनी नेताओं को कहा कि भाजपा को पूरा विश्वास है कि भारत–चीन सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग एवं निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक स्वीकृति से सुलझा लिया जाएगा।

उन्होंने लेह, लद्दाख में चीन की सीमा पर न्योमा ब्लाक में वहां के निवासियों की कठिनाइयों से भी परिचित कराया। इसी प्रकार उन्होंने 37 वर्ष पुराने हुसैन सेलिल सम्बंधी अदालती दस्तावेजों का मुद्दा भी उठाया।

भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी पुनः भारत–पाक बातचीत शुरू करने के पक्ष में है परन्तु यह तभी संभव हो सकता है जब इस्लामाबाद अपने क्षेत्र में सभी आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को समाप्त कर दे और अपनी धरती से आतंकवादी गतिविधियां न चलने दे। अभी तक तो पाकिस्तान ने सीमा–आतंकवादी हमलों के दोषियों तक पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से कोई भी बातचीत करना निरर्थक ही साबित होगा।

भाजपा अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि बिहार में राजग सरकार नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में चीन सरकार के साथ पूरा सहयोग करेगी। चीनी नेताओं ने भी यह स्वीकार किया कि आतंकवाद का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है और बीजिंग इस्लाबाद से ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगी। ■

भाजपा ने की राष्ट्रपति से मांग

राज्यपाल को वापस बुलाओ

Hkkरतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 24 जनवरी को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल से मिलकर कर्नाटक के राज्यपाल श्री हंसराज भारद्वाज को वापस बुलाने की मांग की। भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति देने वाले श्री भारद्वाज के आचरण को पक्षपातपूर्ण और असंवैधानिक करार दिया है। प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार के अलावा 23 सांसद शामिल थे। राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के बाद श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से कर्नाटक के राज्यपाल के आचरण को लेकर शिकायत की। हमने उन्हें बताया है कि पहले दिन से लेकर ही उनका आचरण संविधान के अनुरूप नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भारद्वाज के पक्षपातपूर्ण रवैये के बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मुलाकात करके उन्हें जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह इस मामले में चाहे तो कानूनी विशेषज्ञों से भी सलाह ले सकती हैं। श्री आडवाणी ने कहा कि भारद्वाज ने 25 जून 2009 को पद की शपथ ली थी और इस दिन को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। इसी दिन 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था। श्री आडवाणी ने बताया कि ज्ञापन में कहा गया है कि इस तरह के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण कर्नाटक में राज्यपाल के पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। इसलिए भाजपा राष्ट्रपति से अनुरोध करती है कि वह भारद्वाज को वापस बुला लें जिससे कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था की बहाली हो सके। ■

राज्यपाल का कदम राजनीति से प्रेरित : भाजपा

कर्नाटक के राज्यपाल श्री एचआर भारद्वाज द्वारा मुख्यमंत्री श्री बीएस येदियुरप्पा पर अभियोजन के लिए दी गयी मंजूरी पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम संवैधानिक रूप से अनुचित और राजनीति से प्रेरित है। भाजपा ने राज्यपाल के इस विवादास्पद फ़ैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वह प्रदेश में कांग्रेस की दुर्दशा को संभालने के लिए सक्रिय हो गये हैं और राजभवन को अपनी पार्टी की गतिविधियों का क्षेत्र बना लिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने कहा, ''भाजपा कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा उनके कैबिनेट सहयोगियों के खिलाफ़ अभियोजन की मंजूरी प्रदान करने की कार्रवाई की संवैधानिक तौर पर अनुचित और राजनीति से प्रेरित कदम के तौर पर कड़ी निंदा करती है।''

श्री जेटली ने कहा कि राज्यपाल के तौर पर अपने कार्यकाल में भी उन्होंने भारद्वाज ने गर्व से अपनी राजनीतिक संबद्धता प्रकट की है। भाजपा ने कहा कि जब लोकायुक्त मुख्यमंत्री के खिलाफ़ सभी आरोपों की जांच कर रहे हैं और प्रदेश सरकार ने पहले ही 1994 से भूमि आवंटन के मामले में कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी गठित की है तो राज्यपाल को अभियोजन की मंजूरी से पहले नतीजे का इंतजार करना चाहिए। ■

भ्रष्टाचार व महंगाई पर भाजपा ने भरी हुंकार

laoknnkrk }kjk

Hkkरतीय जनता पार्टी ने देश में भ्रष्टाचार व महंगाई के लिए राज्य और केंद्र की नीतियों को जमकर लताड़ा। भाजपा ने केंद्र को चेतावनी दी कि अगर स्वायत्तता को राज्य में लागू करने की कोशिश हुई तो देशभर में आंदोलन होगा और संसद भी नहीं चलने दी जाएगी।

जम्मू के परेड ग्राउंड में 24 दिसंबर 2010 को आयोजित एकता संकल्प रैली में पूर्व उप प्रधानमंत्री व भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि जम्मू–कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यहां सिर्फ देश का झंडा ही रहेगा। धारा 370 राज्य की सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, इसे जाना ही होगा।

रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल, बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी व भाजपा के कई राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद थे।

कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए श्री आडवाणी ने कहा कि विदेश नीति, आतंकवाद, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विफल रही कांग्रेस ने अपना सारा ध्यान भाजपा पर केंद्रित कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक ही विषय था कि भाजपा का आधार कैसे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के बढ़ने के पीछे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी व पंडित प्रेमनाथ डोगरा जैसे नेता हैं। श्री आडवाणी ने कहा कि जम्मू भाजपा के लिए एक पवित्र स्थान है, हम जम्मू को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले से कांग्रेस ने देश को कलंकित कर दिया। उन्होंने कहा कि 1 लाख 76 हजार करोड़ के घोटाले का कुछ हिस्सा जम्मू–कश्मीर जैसे राज्य को मिल जाए तो सारी मुश्किलें दूर हो जाएं।

वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर मजहब की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जम्मू–कश्मीर में अलगाववाद के लिए कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि आजादी, प्री 1953 स्टेटस के साथ स्वायत्तता की मांग के लिए भी यही पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर इन चारों प्रस्तावों में से एक को भी लागू करने की कोशिश हुई तो भाजपा पूरे देश में आंदोलन करेगी।

इसके बाद श्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य को अलग

दर्जा दिया था, इतिहास ने साबित किया कि उससे अलगाववाद पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य को देश से दूर ले जाने की जो साजिश हो रही है, भाजपा उसे नाकाम बनाने के लिए चट्टान की तरह खड़ी है।

कहा कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह बताएं कि संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु को फांसी क्यों नहीं दी। जम्मू–कश्मीर को भाजपा की प्राथमिकता करार देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर केंद्रित नीतियों का शिकार हो रहे राज्य के लोगों के लिए भाजपा एक सेल बनाएगी, ताकि उनके मसलों को संसद में उठाने के साथ कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। इसके साथ कश्मीर को लेकर भाजपा अपनी समिति भी बनाएगी जो राज्य का दौरा भी करेगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने

तीन घंटे की इस रैली में भाजपा के वरिष्ठ नेता सर्वश्री विनय कटियार, कलराज मिश्र, अनंत कुमार, तनवीर अहमद, भगत सिंह कोशियारी, थावरचंद गहलोत, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिंह मन्हास, प्रो चमन लाल गुप्ता, डॉ. निर्मल सिंह व अशोक खजुरिया आदि भी मौजूद थे।

सरकार सुनिश्चित करे कि विदेशों में रखा काला धन वापस आयेगा : आडवाणी

eम्बई में आयोजित महासंग्राम रैली को सम्बोधित करते हुए राजग के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने विदेशों में भारतीयों द्वारा जमा काले धन के खाताधारियों के नाम और इससे सम्बंधित सूचना को सार्वजनिक करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को स्वागत योग्य बताया।

श्री आडवाणी ने केन्द्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करे कि विदेशों में जमा काले धन को भारत में वापस लाएगी और इस अपराध में सम्मिलित लोगों को दण्डित किया जाएगा। विदेशों में जमा काला धन भ्रष्टाचार से जुड़ा एक अहम मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने 2009 में ही इस काले धन के सम्बंध में कहा था कि जो धन गलत तरीकों से अर्जित करके स्विट्जरलैण्ड जैसे देशों में रखा गया है जहां बैंकिंग कायदे कानून गोपनीय खाते की अनुमति देता है को वापस लाया जाए।

आर्थिक मंदी के समय अमरीका और जर्मनी जैसे देशों ने विदेशों में जमा अपने देशों का काले धन को वापस लाने के लिए कानून पास किया है। जब राजग ने ऐसा कानून बनाने का मुद्दा भारत में उठाया तो सत्तारूढ़ दल यूपीए ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐसा हमारे लिए संभव नहीं है।

क्वात्रोच्चि का गांधी परिवार के साथ गहरा सम्बंध था : गडकरी

महासंग्राम रैली को मुम्बई में संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने केन्द्र और राज्य की कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार और महंगाई के लिए जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की सरकार कानून बनाकर जनता को लूटती है। जैसे राष्ट्रमण्डल खेल में यह नियम था जो ठेकेदार अनुभव रखेगा उसी को ठेकेदारी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ सारे अनुभवी ठेकेदारों को बाहर रखा गया और जिनका अनुभव नहीं था कांग्रेस के

नेताओं ने उनसे सांठगांठ करके राष्ट्रमण्डल खेल में जमकर लूट मचाई।

श्री गडकरी ने आगे कहा कि लाखों किसानों ने आत्महत्या की और एक रिपोर्ट के अनुसार अपने देश के 70 प्रतिशत लोगों की एक दिन की आमदनी बीस रूपए से कम है। दूसरी तरफ कृषि मंत्री शरद पवार अनाज को सड़ा रहे हैं। अनाज के रख–रखाव के लिए गोदाम नहीं बनवा रहे हैं। अनाजों की जमाखोरी पर कोई रोक नहीं लगायी जा रही है।

भ्रष्टाचार पर बोलते हुए श्री गडकरी ने कहा कि मेरे पास सारा साक्ष्य है जो सिद्ध करता है कि वीना चढ्ढा के लड़के का खाता है और वे साक्ष्य यह भी सिद्ध करते हैं कि क्वात्रोच्चि का गांधी परिवार से गहरा सम्बंध है।

उन्होंने रैली में राजग द्वारा की जा रही जेपीसी की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि यदि हम लोग 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले में संयुक्त संसदीय जांच समिति की मांग कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। कांग्रेस भयभीत है कि कहीं और घोटालों का खुलासा न हो जाए। राजग के कार्यवाहक संयोजक श्री शरद यादव ने कहा कि यह लड़ाई न्याय के लिए है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राजनीतिक दल 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले में जेपीसी जांच चाहते हैं। यहां तक की कांग्रेस गठबंधन में भी जेपीसी जांच 2जी घोटाले और कॉमनवेल्थ घोटालों में चाहती है। लेकिन 206 सीटों वाली कांग्रेस जेपीसी से कतरा रही है।

शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कांगेस और उसके सहयोगी दल को लाज–शर्म नहीं है। उन्होंने रैली को सम्बोधित करते हुए आगे कहा कि एक अर्थशास्त्री देश का प्रधानमंत्री है और एक किसान का बेटा कृषि मंत्री है फिर भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं और महंगाई अनियंत्रित रूप से बढ़ती जा रही है।

आदर्श सोसाइटी का हवाला देते हुए श्री ठाकरे ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि बिल्डिंग गिराई जाए लेकिन लवासा के मुद्दे पर देखना है क्या होता है। कहा जा रहा है कि शरद पवार लवासा में सम्मिलित है शायद ही इस मामलें में कुछ हो। श्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी कि यदि आदर्श सोसाइटी नहीं गिराई तो आम आदमी को कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ■

यूपीए शासन में लुट रहा है जन-धन : नितिन गडकरी

गत 17 जनवरी को ओड़िशा की राजधानी भुवनेश्वर में लगभग 3 लाख लोगों का ज्वार उमड़ पड़ा। भाजपा की महासंग्राम रैली में जनता ओड़िशा के कोने–कोने से आयी हुई थी। भारत–माता की जय और जय श्रीराम के नारों से राजधानी गूंज उठी। लेकिन जगह–जगह से आयी जनता काफी अनुशासित रही।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने उस विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र की कांग्रेस सरकार और राज्य की बीजद की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा ही देश में एक विकल्प है जो सुशासन दे सकता है।

उन्होंने कहा कि आदर्श हाउसिंग घोटाले, राष्ट्रमंडल खेल घोटाले, महंगाई ने केन्द्र में सत्तारूढ कांग्रेस की पोल खोल दी है। उसी तरह राज्य की नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली सरकार वेदांता, पोस्को और दूसरे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने की दोषी है। नवीन पटनायक की सरकार नैतिक रूप से शासन में बने रहने की हकदार नहीं है। वेदांता के मामलों में न्यायालय की टिप्पणी से सरकार शासन करने की नैतिक अधिकार गंवा चुकी है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य में हुई मनरेगा घोटालों में सीबीआई जांच के लिए कहा है।

आगे कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीब किसानों और जनता के प्रति जरा भी गंभीर नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाली पार्टी है। इसके शासनकाल में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता धनी होते गए हैं और आम जनता गरीब होती चली गई। कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियों के कारण लगभग 10 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 70,000 करोड़ रूपए हवाईजहाज खरीदने के लिए हैं लेकिन किसानों को आत्महत्या से रोकने के लिए पैसे नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार ने दिन–दहाड़े देश को लूटा है। उन्होंने आगे कहा कि बोफोर्स घोटाले में आरोपी क्वात्रोच्चि का कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से काफी नजदीकी है।

श्री गडकरी ने केन्द्र द्वारा मुख्य सतर्कता आयुक्त जो कि भ्रष्टाचार का आरोपी है। उसको बचाया जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में पी.जे. थॉमस की नियुक्ति का विरोध किया था। ज्ञातव्य है कि विपक्ष का नेता तीन सदस्यीय नियुक्ति मण्डल का सदस्य होता है। फिर भी सुषमा स्वराज के असहमति के बावजूद थॉमस की नियुक्ति कांग्रेस ने सारे नियम कानून को ताक पर रखकर की। श्री गडकरी ने कहा कि फिर नियुक्ति मण्डल का मतलब क्या है। इससे साफ होता है कि कांग्रेस नियम–कानूनों का खुल्लेआम उल्लघंन करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है।

उन्होंने ओड़िशा की नवीन पटनायक वाली सरकार को कहा कि यह सरकार सभी मोर्चों पर असफल है। यह भी राज्य को लूटने में कांग्रेस से पीछे नहीं है। नवीन पटनायक का नारा है, 'तुम दिल्ली में लूटों और हम ओड़िशा में लूटेंगे।' श्री गडकरी ने कहा कि मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब तक लक्ष्मीनन्द सरस्वती के हत्या के आरोपी पकड़े क्यों नहीं गए। क्या न्याय में इसलिए देर हो रहा है कि स्वामी जी हिन्दू थे?

ओड़िशा के लोग का विश्वास बीजेडी से उठ गया है। इस अवसर पर गडकरी ने आगे किसी भी तरह के गठबंधन से इंकार किया। और कहा कि भाजपा ओड़िशा में अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि यदि भाजपा सत्ता में आयेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त और विकास केन्द्रित शासन देगी इस रैली को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री जुएल ओराम, राष्ट्रीय महासचिव धर्मेन्द्र प्रधान, ओड़िशा भाजपा प्रभारी श्री संतोष गंगवार, श्री विजय महापात्रा, श्री के.बी. सिंह देव सहित अनेक पार्टी नेताओं ने

अलगाववाद बनाम राष्ट्रवाद लड़ाई जारी रहेगी....

l;tho flUgk dh fo'k"k fjikVZ

राष्ट्रीय एकता यात्रा ने अपनी सार्थकता साबित कर दी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस यात्रा ने कांग्रेसनीत केन्द्र सरकार और कांग्रेस–नेशनल कांफ्रेंसनीत जम्मू–कश्मीर सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगा दिया है। कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति और उमर अब्दुल्ला की अलगाववादपरस्त नीतियों का पर्दाफाश हो गया। यात्रा के दौरान भाजयुमो को जिस तरह से स्थानीय समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिला, उससे स्पष्ट हो जाता है कि कश्मीर की समस्या से भारत का हर नागरिक चिंतित है।

देश के एक जिम्मेदार युवा संगठन के नाते भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और तय किया कि देश की एकता एवं अखण्डता के लिए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में कोलकाता से श्रीनगर तक (12 जनवरी 2011 से लेकर 26 जनवरी 2011) 'राष्ट्रीय एकता यात्रा' निकालेंगे और गणतंत्र दिवस के दिन लालचौक पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे।

भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कोलकाता (पश्चिम बंगाल) से 'राष्ट्रीय एकता यात्रा' का शुभारंभ किया, क्योंकि यहां की माटी युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस और डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी की कर्मस्थली रही है। यह यात्रा डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी की जन्मस्थली से उनके बलिदान स्थली तक युवा दिवस (12 जनवरी 2011) से गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2011) तक निकाली गयी। इस दौरान 11 राज्यों में 150 से अधिक जन–जागरण सभाएं आयोजित की गयी और यात्रा ने तीन हजार किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। इस क्रम में जगह–जगह देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हुए जवानों के परिवारों का सम्मान किया गया।

12 जनवरी–पश्चिम बंगाल

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर को राष्ट्रध्वज तिरंगा सौंप कर 'राष्ट्रीय एकता यात्रा' को रवाना किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यद्यपि जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तथा कुछ अलगाववादी भले ही यात्रा का विरोध कर रहे हों, परन्तु यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वह

यात्रा का एक जीवंत नजारा

राष्ट्रीय एकता यात्रा के दौरान कंपकपाती ठंड में भी जनज्वार उमड़ रहा है। हाथों में राष्ट्रध्वज तिरंगा थामे युवा कार्यकर्ताओं का हुजूम आगे बढ़ रहा है। 'कश्मीर जाएंगे–तिरंगा फहराएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी–वह कश्मीर हमारा है, वंदे मातरम्, भारत माता की जय' के नारों से यात्रा गूंज रही है। सबसे आगे रथ पर भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर सवार हैं। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में खड़े वृद्ध व महिलाएं रथ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अपार जनसमूह ने मानो यात्रा के स्वागत के लिए पलकें बिछा दी हो। अनुराग नारे लगाकर व हाथ हिलाकर सबका अभिवादन कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं। रथ के पीछे कारों और मोटरसाइकिलों का लंबा काफिला भी साथ चल रहा है। जगह–जगह स्थानीय लोगों द्वारा मिठाई और फूलों से यात्रा में शामिल युवाओं का स्वागत किया जा रहा है। यात्रा पूरे उत्साह के साथ अपने निर्धारित मार्ग पर चल रह रही है। यात्रा मार्ग पोस्टर, बैनर और स्टीकरों से सजा हुआ है। यात्रा के दौरान अनुराग युवाओं से सीधा संवाद करते हैं और उन्हें राष्ट्रीय एकता यात्रा का उद्देश्य समझाते हैं।

देश के किसी भी कोने पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय एकता यात्रा को राष्ट्रीय महत्व का बताते हुए कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य पवित्र है और इसे निकालने का मकसद है भारतीय एकता को मजबूती प्रदान करना। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्मृति ईरानी, सांसद श्री चंदन मित्रा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री राहुल सिन्हा, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव श्री मनोरंजन मिश्र सहित अनेक वरिष्ठ युवानेता उपस्थित थे।

13 जनवरी– पश्चिम बंगाल

राष्ट्रीय एकता यात्रा पर निकले श्री अनुराग ठाकुर का आसनसोल में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्री अनुराग ठाकुर ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जयंत मुखर्जी के पिता श्री दिलीप मुखर्जी को सम्मानित किया। इस दौरान क्षेत्र के मुस्लिम युवाओं का जत्था भी रथ के साथ यात्रा के रूप में न केवल शामिल हुए बल्कि भाजपा में शामिल होकर एक नया संदेश दिया।

14 जनवरी– झारखंड तथा बिहार

यात्रा के तीसरे दिन हजारीबाग से शुरू हुई यात्रा का बाराचट्टी गैवान बांध सहित कई जगहों पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर गया के सांसद हरि मांझी, बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार, विधायक संजय यादव, भाजपा अध्यक्ष दिनेशानन्द गोस्वामी सहित भारी संख्या में लोग यात्रा के साथ चले। यात्रा के दौरान हजारीबाग के बरही और गया के आजाद पार्क में हुई जनसभा को भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर ने और पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने संबोधित किया।

15 जनवरी– उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय एकता यात्रा चौथे दिन पटना से चलकर उत्तर प्रदेश पहुंची। दोनों राज्यों की सीमा पर रथ में सवार भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत उत्तर प्रदेश भाजयुमो अध्यक्ष हरीश द्विवेदी की अगुवाई में किया गया। इसके पहले पटना से

वरिष्ठ भाजपा नेता गिरफ्तार

जम्मू–कश्मीर सरकार के तमाम अवरोधों को दूर करते भाजयुमो की 'राष्ट्रीय एकता यात्रा' 25 जनवरी की शाम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जम्मू एवं कश्मीर की सीम प्रवेश कर गई। प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद पार्टी वरिष्ठ नेताओं–लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सु स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेट राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार, मोर्चा के राष्ट्रीय अध श्री अनुराग ठाकुर सहित अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार लिया गया। भाजयुमो कार्यकर्ता 'भारत माता की ज फहराएंगे' के नारे लगाते पंजाब की तरफ से रावी न कश्मीर में प्रवेश कर गए। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को अ के बाद भाजपा नेताओं ने कठुआ के शहीद चौक पर

राजनाथ सिंह अन

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को जम्मू कश्म महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर दो दिन अनशन श्री विजेन्द्र गुप्ता भी अनशन पर थे। भाजपा के राष्ट्रीय अ को श्री सिंह को फल का रस पिलाया और उनसे अन

गिरफ्तार

धों को दूर करते हुए
जनवरी की शाम में
कश्मीर की सीमा में
समय बाद पार्टी के
नेता श्रीमती सुषमा
श्री अरुण जेटली,
र्वा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
व कार्यकर्ताओं को
य में गिरफ्तार कर
त माता की जय' और श्लाल चौक जाएंगे, तिरंगा
रफ से रावी नदी पर बने पुल को पार कर जम्मू एवं
र्यकर्ताओं को अगले दिन रिहा कर दिया गया। रिहाई
शहीद चौक पर तिरंगा फहराया।

ा सिंह अनशन पर

ध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय एकता यात्रा में शामिल
ों को जम्मू कश्मीर में रोके जाने के खिलाफ राष्ट्रपिता
दो दिन अनशन पर रहे। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष
जपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 26 जनवरी
और उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह किया।

सुबह रवाना हुई यात्रा आरा पहुंची, जहां स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के स्मारक के पास जाकर श्री अनुराग ठाकुर ने उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की। रास्ते में यात्रा का जगह–जगह स्वागत हुआ। बक्सर और गाजीपुर में हुई बड़ी सभाओं में भाजयुमो अध्यक्ष ने केन्द्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बीते छह माह में चल रही हिंसा और पथराव की घटनाएं रोकने में केन्द्र और कश्मीर सरकार पूरी तरह विफल रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश सीमा पर उजियारपुर में भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वामी सहजानंद जी की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण किया। वहां से रवाना होकर यात्रा गाजीपुर पहुंची। वहां हुई सभा को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कलराज मिश्र ने भी संबोधित किया।

16 जनवरी– उत्तर प्रदेश

भाजयुमो के राष्ट्रीय एकता यात्रा का कांग्रेस के गढ़ अमेठी में भव्य स्वागत हुआ। वहां आयोजित सभा में उपस्थित भीड़ इस बात की गवाही दे रही थी कि गांधी परिवार की इस विरासत से अब उनका मोह भंग हो रहा है। अमेठी की उपेक्षा पर सवाल खड़ा करते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो नेता अपने संसदीय क्षेत्र की दशा नहीं सुधार पाया हो उससे देश में सुधार लाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। सुबह वाराणसी से शुरू हुई यात्रा जौनपुर से सुल्तानपुर होते हुए अमेठी पहुंची। अमेठी में सिख समाज की ओर से श्री अनुराग ठाकुर को तलवार भेंट की गई। अमेठी पहुंची यात्रा को रास्ते में रोककर पचहत्तर वर्षीय वृद्धा शांति देवी ने भाजयुमो अध्यक्ष को तिरंगा सौंपकर उन्हें यात्री की सफलता के लिए आशीर्वाद दिया। यात्रा का जलालपुरए चौपानी, सिफौली, जफनाबाद सहित रास्ते में पड़ने वाले छोटे गांव और कस्बों में भी भव्य स्वागत किया गया।

17 जनवरी– उत्तर प्रदेश

पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर से शुरू हुई राष्ट्रीय एकता यात्रा आज छठवें दिन कानपुर पहुंची। कानपुर पहुंचने पर विशाल सभा को सम्बोधित करते

हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले पं. जवाहर लाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती और अब राहुल और उमर की दोस्ती देश को ले डूबेगी। इस अवसर पर आम सभा को भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने भी संबोधित किया।

18 जनवरी– मध्यप्रदेश

झांसी से सुबह रवाना हुई राष्ट्रीय एकता यात्रा सातवें दिन दतिया पंहुची। यहां आयोजित सभा में भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर ने तिरंगा यात्रा का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यात्रा को रोकने की धमकी देने वाले तथा इसका विरोध करने वाले राष्ट्रद्रोही हैं, उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। रास्ते में मध्य प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा और भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्री जितू जिराती ने भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर का स्वागत किया तथा राष्ट्रीय एकता यात्रा के काफिले पर पुष्प वर्षा की गई।

19 जनवरी– उत्तर प्रदेश, राजस्थान

पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश होते हुए यात्रा आठवें दिन फिर उत्तर प्रदेश पहुंची। आगरा में राष्ट्रीय एकता यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहां से सुबह रवाना होकर यात्रा राजस्थान के भरतपुर पहुंची। वहां आयोजित जनसभा में श्री ठाकुर ने केन्द्र सरकार से विस्थापित कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करने की मांग की। राष्ट्रीय एकता यात्रा के मथुरा पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत हुआ। वहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अनंत कुमार ने जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को मशविरा दिया कि वह राष्ट्रीय एकता यात्रा को रोकने की बजाय मुख्यमंत्री की हैसियत से तिरंगे का स्वागत करने आएं।

20 जनवरी– दिल्ली

राष्ट्रीय एकता यात्रा बदरपुर बार्डर के रास्ते दिल्ली पहुंची। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने पुष्प बरसाकर यात्रा का जोरदार स्वागत किया। नई दिल्ली स्थित कांस्टिट्यूशन क्लब परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता यात्रा अलगाववादी तत्वों को भड़काने के लिए नहीं बल्कि उन्हें ललकारने के लिए निकाली गई है। श्री आडवाणी ने एकता यात्रा की सफलता के प्रतीक स्वरूप भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर को तिरंगा भेंट किया।

21 जनवरी– दिल्ली, हरियाणा

भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लालचौक में तिरंगा फहराने का न्योता देते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला भारत के संविधान के अनुसार ही जम्मू एवं कश्?मीर के मुख्यमंत्री बने हैं और जम्मू एवं कश्मीर में तिरंगे के सम्मान की रक्षा करना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। पानीपत पहुंची यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहां आयोजित जनसभा में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव श्री जे.पी. नड्डा एवं भाजपा सांसद श्री नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हुए। इससे पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय के क्रांति चौक पर श्री ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया।

22 जनवरी– पंजाब

चंडीगढ़, मोहाली, रोपड़ और अनंतपुर साहिब में जनसभा को सम्बोधित करते हुए भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को चुनौती दी कि वह अलगाववादी ताकतों को लेकर अपनी दोहरी नीति स्पष्ट करें।

23 जनवरी– पंजाब–हिमाचल प्रदेश

राष्ट्रीय एकता यात्रा का होशियारपुर, अमृतसर और जालंधर में भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय एकता यात्रा में भाजपा राष्ट्रीय सचिव श्री नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के कानून मंत्री भी शामिल हुए। यात्रा का स्वागत शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने भी किया। इस अवसर पर भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के कथन पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता यात्रा के संबंध में में आया उनका बयान लोकतंत्र का गला घोंटने वाला है।

24 जनवरी– पंजाब

भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद श्री अनुराग ठाकुर ने हजारों युवाओं की शांतिपूर्ण राष्ट्रीय एकता यात्रा को रोकने के केन्द्र एवं जम्मू कश्मीर सरकार के प्रयासों की निंदा की। अमृतसर में उन्होंने प्रधानमंत्री और जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री से सवाल किया कि वह देश को बतायें कि पिछले साल ईद के मौके पर सुरक्षा बलों और मीडिया की मौजूदगी में पाकिस्तान का झंडा फहराने की अनुमति क्यों दी गई। श्री ठाकुर ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद जालियांवाला बाग शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की शहादत को नमन किया। महापौर श्वेत मलिक ने रथ के आगे नारियल फोड़कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री श्री नवजोत सिंह सिद्धू और विधायक श्री अनिल जोशी भी मौजूद रहे।

इस यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शांता कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री सर्वश्री अनंत कुमार, जगत प्रकाश नड्डा एवं धर्मेन्द्र प्रधान, राष्ट्रीय सचिव सुश्री वाणी त्रिपाठी तथा जम्मू–कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री शमशेर सिंह मन्हास की सहभागिता उल्लेखनीय रही। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता रैली के प्रभारी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री मनोरंजन मिश्र थे। ■

लालचौक पर तिरंगा फहराने के लिए हर बलिदान को तैयार : अनुराग ठाकुर

भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर सांसद ने 12 जनवरी को कोलकाता से राष्ट्रीय एकता यात्रा का शुभारंभ किया, जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया। यात्रा का समापन 26 जनवरी को लाल चौक, श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर सम्पन्न होगी। श्री अनुराग ने अपने राजनैतिक जीवन की यात्रा 2008 में लोकसभा के उपचुनाव में विजय हासिल करते हुए हिमाचल प्रदेश की हम्मीरपुर संसदीय निर्वाचन से सबसे भारी बहुमत प्राप्त कर एक रिकार्ड कायम किया। इस क्षेत्र में सशस्त्र सेना के सबसे अधिक संख्या में लोग रहते हैं। श्री अनुराग ठाकुर के सामने देश के युवाओं में जोश भरने और राष्ट्रीय भावना को प्रज्जवलित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य है। श्री अनुराग ठाकुर ने एक बड़ी साहसिक चुनौती को स्वीकारा है। उनके संकल्प ने युवकों के मन में एक नई स्फूर्ति व शक्ति का संचार किया है और राष्ट्र भावना की अलख जगाई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की धमकी के बावजूद भी श्री ठाकुर ने पूरे विश्वास और संकल्पबद्ध होकर घोषणा की है कि ''चाहे जो भी हो, हम तो अपने राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।''

यात्रा को लेकर भाजपा साहित्य और प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक Jh vEckpj.k of'k"B *ने इस यात्रा पर जाने से पूर्व ''कमल संदेश'' के लिए नई दिल्ली में उनसे साक्षात्कार किया। कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं:*

किस बात ने आपको इस यात्रा के लिए अभिप्रेरित किया?

अलगाववादियों तथा पाक–समर्थित तत्वों के कार्यों ने भारत की एकता और अखण्डता को भारी खतरे में डाल दिया है। मुझे इस यात्रा की प्रेरणा इसी बात से मिली कि हम यह फिर से बता दें कि जम्मू और काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और दुनिया की कोई ताकत इसे हमसे छीन नहीं सकती।

राष्ट्रीय एकता यात्रा की प्रमुख विशेषताएं बताइए?

स्वामी विवेकानन्द, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी की जन्मस्थली और कर्मस्थली कोलकाता से स्वामी विवेकानन्द के जन्मदिवस 12 जनवरी से यात्रा की शुरूआत हुई है जो 26 जनवरी 2011 को गणतंत्र दिवस पर 11 राज्यों से 3066.54 कि. मी. की यात्रा तय करते हुए श्रीनगर में (डॉ. मुकर्जी बलिदानस्थली) लालचौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ सम्पन्न होगी। रास्ते में लगभग 150 जनसभाएं आयोजित की जाएंगी और यात्रा के दौरान विभिन्न स्थलों पर शहीदों के परिवारों का सम्मान किया जाएगा। 25 जनवरी को जम्मू में एक विशाल रैली होगी जिसमें लाखों युवक काश्मीर के लोगों के साथ, विशेष रूप से युवा वर्ग अपनी एकता का प्रदर्शन कर इसमें भाग लेंगे।

आपके उद्देश्य क्या हैं?

हमारे उद्देश्यों में अनुच्छेद 370 को समाप्त करना; आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट में कोई संशोधन न हो; पाक–अधिकृत काश्मीर को वापस लेने के भारतीय संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का सम्मान किया जाए; काश्मीर युवाओं के लिए सुरक्षित, महफूज और शोषण मुक्त जीवन सुनिश्चित किया जाए; काश्मीर से बाध्य होकर भागे काश्मीरी

पंडितों को सम्मानपूर्वक काश्मीर में उनका पुनर्वास हो; जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के साथ राजनैतिक और आर्थिक भेदभाव समाप्त हो और सभी तीनों क्षेत्रों के लिए एक समान विकास सुनिश्चित किए जाएं। किसी भी समाधान को तैयार करते हुए संविधान की भाषा और भावना का आदर किया जाए।

लगभग एक सप्ताह पूर्व शुरू हुई आपकी यात्रा के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

बस इतना कहूंगा कि यह विलक्षण रही। मैंने, जिस उद्देश्य से यात्रा की शुरूआत की उसके प्रति लोगों में, विशेष रूप से युवाओं में, असीम उत्साह और जोश देखा है। यात्रा को भारी समर्थन मिला है और कभी–कभी तो हमारे कारवां को इस कारण छह–छह घण्टे तक देर का सामना करना पड़ा है। लगभग सभी स्थलों पर रैलियों में 25/30 हजार की भीड़ मौजूद रही है।

जम्मू और काश्मीर के मुख्यमंत्री ने आपकी पार्टी को सलाह दी है कि यात्रा बंद कर दें क्योंकि उनकी राय में यह राज्य में शान्ति के लिए खतरा होगी।

विचित्र बात है। उन्हें उन अलगाववादियों और राष्ट्र–विरोधी तत्वों की हरकतों से खतरा दिखाई नहीं पड़ता है जिन पर उन्हें अंकुश लगाना चाहिए। उन्हें तब शांति के लिए खतरा महसूस नहीं होता जब हुर्रियत और अन्य नेता जो सदैव विद्रोही गतिविधियों में लगे रहते हैं और जो भारतीय संविधान में निहित वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठा कर खुलेआम पृथक्करण की हिमायत करते रहते हैं। जब वे संविधान को चुनौती देते हैं, जिसमें जम्मू और काश्मीर को भारत मंच के साथ मान्यता दी तब उमर साहब शांति महसूस करते हैं। परन्तु, अब वह श्रीनगर में पूर्ण शांति के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने की हमारी इच्छा को लेकर खतरा महसूस करने लगे हैं। जम्मू और काश्मीर में कांग्रेस–एनसी सरकार और केन्द्र में यूपीए सरकार अलगावादियों को भारत के किसी भी भाग में विद्रोही गतिविधियां करने की स्वतंत्रता दे रहे हैं, जिसमें दिल्ली भी शामिल है परन्तु वे श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दिखाने की स्वतंत्रता से हमें वंचित रखना चाहते हैं।

अलगाववादियों ने भी आपकी यात्रा पर धमकी दी है?

मुझे इस की जरा भी परवाह नहीं है। यह तो राज्य और केन्द्र सरकार को इन धमकियों और उनकी हरकतों से निपटना है। पूरी तरह से राष्ट्रवादी होने के नाते मैं और भाजयुमो कार्यकर्ता अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने एवं अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से वैध राष्ट्रीय कर्त्तव्य निभाने के लिए श्रीनगर जा रहे हैं। यह राज्य और केन्द्र सरकार दोनों का फर्ज है कि वे हमें सुरक्षा प्रदान करें और अन्य लोगों की राष्ट्र–विरोधी हरकतों को रोकें। इसके लिए हम कोई भी बलिदान देने को तैयार हैं, चाहे हमारा जीवन ही क्यों न राष्ट्र की सम्प्रभुता और अखंडता की खातिर बलिदान हो जाए। अलगाववादी और सरकार चाहे जो कहें, हम अपने राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प हैं, चाहे जो भी हो जाए।

भाजयुमो अध्यक्ष के नाते सीधा टकराव कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से है। इसे आप किस रूप में देखते हैं?

राहुल गांधी अधिकाधिक युवाओं को राजनीति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं भी इसे अपने ढंग से कर रहा हूं। जहां तक प्रयास की बात है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हम दोनों के प्रयास एक–दूसरे के पूरक हैं।

देश के युवा राहुल के प्रति आकर्षित हैं?

यह केवल मीडिया में बढ़ा चढ़ा कर कहने की बात है। राहुल ने युवाओं के लिए किया क्या है जो वे उनके प्रति आकर्षित हो जाएंगे? उन्होंने निर्धनता–उन्मूलन और युवाओं में बेरोजगारी हटाने के लिए क्या किया है? किसी दलित के घर जाने से दलित समुदाय की गरीबी मिटती नहीं है। लगता है कि आज युवा कांग्रेस समाप्ति की दिशा में है और केवल राहुल दिखाई पड़ते हैं। युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, लोग तो यह भी नही जानते।

रिपोर्टों के अनुसार, भारत की आधी जनसंख्या, जिसमें आधे से अधिक युवा लोग हैं, अपने जीवनयापन के लिए एक दिन में 20 रूपए भी खर्च नहीं कर सकते हैं। मैं अपने अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और राहुल दोनों के सामने चुनौती रखता हूं कि वे इन लोगों के लिए परिवार के मॉडल बजट तैयार करके दिखा दें ताकि उन्हें दिन में कम से कम दो जून की रोटी तो नसीब हो सके।

आप राहुल गांधी की उपलब्धियों का किस प्रकार आकलन करते हैं?

इसका आकलन मैं नहीं कांग्रेस करे और लोग तो स्वयं ही

शेष पृष्ठ 24 पर

कश्मीर में तिरंगा फहराना एक अपराध?

✍ v- p- of'k"B

bसे एक संयोग ही कहिये कि एक ओर तो पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने जनता को चेतावनी दी है कि पंजाब के राज्यपाल सलमान तासीर की हत्या पर शोक न करें तो दूसरी ओर कश्मीर के पृथकतावादी तथा कट्टरवादियों ने चेतावनी जारी कर दी कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा श्रीनगर के लाल चौक में गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय झंडा फैहराने के अपने इरादे से बाज आये। उन्होंने इसके गम्भीर परिणाम के प्रति चेताया है।

किसी की मृत्यु पर शोक होना एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है चाहे मृतक हमारा दुश्मन ही क्यों न हो। इसलिये किसी की मृत्यु पर शोक करने पर किसी को किसी प्रकार का बुरा नहीं मनाना चाहिये। इसी प्रकार अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपना सम्मान प्रकट करना विश्व के हर नागरिक का कर्त्तव्य है और यदि एक नागरिक ऐसा करता है तो दूसरे का इस पर उत्तेजित होने वाली बात समझ नहीं आती। कश्मीर में कुछ ऐसे लोग अवश्य हैं जो कभी चुनाव लड़कर जनता में उनका कितना प्रभाव है यह दिखाने की हिम्मत कभी नहीं की। पिछले दो चुनाव ऐसे हुये हैं जिनकी विदेशों में भी प्रशंसा हुई कि वह साफ–सुथरे व निष्पक्ष थे। पर कश्मीरी जनता के हितों के कुछ स्वयंसिद्ध ऐसे ठेकेदार हैं जो बिना बात के ही भड़क उठते हैं।

चलो पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वह उनका अपना अन्दरूनी मामला है। पर जो भारत में हो रहा है वह तो बिलकुल ही अजीब है। हमारे तथाकथित सैकुलरवादी, उदारवादी सज्जन, संगठन व मीडिया तो ऐसे व्यवहार कर रहे है मानो भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कोई बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा है। वह सब भाजयुमो को अपना इरादा त्याग देने की सलाह दे रहे हैं। कोई यह कहने

की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि अलगाववादियों को ऐसा कहने और धमकी देने का कोई अधिकार नही है। उन्हें संविधान और कानून की धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिये।

मुख्यमन्त्री श्री उमर अबदुल्ला समेत इन महानुभावों को तब तो शान्ति को कोई खतरा महसूस नहीं होता जब कुछ लोग हर तीसरे दिन हड़ताल, विरोधमार्च व प्रदर्शन, पत्थरबाज़ी और प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति के आगमन पर कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा कर देते हैं। पर जब भाजयुमो तिरंगा फैहराने का निर्णय लेती है तो उन्हें शान्ति को खतरा दिखाई देता है। यह ढोंग तो कानून का सम्मान करने वाली साधारण जनता के गले नहीं उतरता।

राष्ट्रीय झण्डा फहराने और उसका सम्मान करने पर तो किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिये। यदि हमारा शत्रु भी हमारे झण्डे का सम्मान करे तो हमें एतराज़ नहीं उसका कृतज्ञ ही होना चाहिये।

जम्मू व कश्मीर भी भारत का एक अभिन्न, अविभाज्य अंग है जैसा की

कोई अन्य प्रदेश। श्रीनगर उसकी राजधानी है और लालचौक एक सार्वजनिक स्थान जहां कोई भी जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज के साथ तो कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जा सकता है। तो फिर उस स्थान पर किसी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फैहराने के इरादे पर इतना हो–हल्ला क्यों?

लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फैहराने के भाजयुमो के कदम का विरोध करने वाले अप्रत्यक्ष रूप से क्या अलगाववादी व आतंकवादी तत्वों की ही पीठ नहीं ठोक रहे?

अलगाववादियों व आतंकवादियों की धमकियों के आगे झुकने से तो प्रश्न यह भी उठता है कि कश्मीर में तूती किसकी बोलती है –– सरकार की जिसके पास जनादेश है या उनका राज चलता है जिन्होंने कभी जनादेश प्राप्त करने की हिम्मत नहीं दिखाई?

देखा जाये तो अपना उल्लू सीधा करने के लिये अबदुल्ला परिवार समय–समय पर परिधान की तरह अपना तर्क, अपनी भाषा और अपनी चाल–ढाल बदलता रहता है। यही कारण है कि अपने राजनैतिक जीवनकाल में इस परिवार ने कोई ऐसा दल नहीं छोड़ा है जिसके साथ अपनी डोरी न बांधी हो। उनका हाल भी वैसा ही है जैसा कि तलाक पा लेने के बाद उस व्यक्ति का जो अपने आपको सही ठहराता है और अपने दूसरे साथी को गलत। कांग्रेस, वीपी सिंह के जनता दल, चन्द्रशेखर व इन्द्र कुमार गुजराल और छः वर्ष तक भाजपा–नीत राजग के साथ भी। उमर अब्दुल्ला तो राजग समय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मन्त्री भी रह चुके हैं। लगता है उन्हें तो अपनी सत्ता से लेना–देना है, उसूलों से नहीं।

पिछले दिनों जब उन्हें अपनी कुर्सी खिसकती दिखी तो चले गये अलगाववादियों की शरण में और उनकी भाषा में ही कह दिया कि कश्मीर का भारत के साथ विलय नहीं हुआ। यदि विलय नहीं हुआ तो वह स्वयं राजग के समय और आज उनके पिता केन्द्र में

~~~~~~~~~~

लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के भाजयुमो के कदम का विरोध करने वाले अप्रत्यक्ष रूप से क्या अलगाववादी व आतंकवादी तत्वों की ही पीठ नहीं ठोक रहे? अलगाववादियों व आतंकवादियों की धमकियों के आगे झुकने से तो प्रश्न यह भी उठता है कि कश्मीर में तूती किसकी बोलती है –– सरकार की जिसके पास जनादेश है या उनका राज चलता है जिन्होंने कभी जनादेश प्राप्त करने की हिम्मत नहीं दिखाई?

~~~~~~~~~~

मन्त्री किस हैसियत से हैं? उन्होंने हिमाचल प्रदेश व अन्य स्थानों पर सम्पत्ति कैसे खरीद रखी है?

एक मुख्यमन्त्री का तो कर्त्तव्य बनता है कि वह शान्ति व्यवस्था बनाये रखे। न्यायप्रेमियों तथा कानून का पालन करने वालों को सुरक्षा प्रदान करें और कानून का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटें। पर वह कर इसका उलट रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की मुख्यमन्त्री की कुर्सी तो अभी भी सुरक्षित नहीं है। इसलिये एक बार फिर अलगाववादियों की भाषा बोलते हुये वह उलट भाजयुमो को ही दोषी ठहरा रहे हैं मानो लाल चौक पर तिरंगा फहराने की बात कर भाजयुमो कोई बड़ा अपराध करने जा रही हैं। वह फरमाते हैं कि भाजयुमो का तिरंगा फहराना एक ''भड़काऊ कृत्य'' होगा और ऐसा कर भाजपा ''कश्मीर में आग भड़काना चाहती है''।

भाजपा शान्तिपूर्ण ढंग से तिरंगा फहरा कर अपना एक संवैधानिक कर्त्तव्य निभा रही है पर यह मुख्यमन्त्री और अलगाववादी दोनों को ''भड़काऊ'' कदम लग रहा है। पर जो अलगाववादी धमकी दे रहे हैं वह उन्हें एक न्याय व कानून प्रिय नागरिक का सुसंस्कृत व्यवहार लग रहा है। यदि उनकी सोच ही ऐसी है तो क्या किया जा सकता है?

अपने आप को लाचार जताते हुये मुख्यमन्त्री आगे फरमाते हैं कि ऐसी स्थिति में कुछ हो गया तो ''मुझे ज़िम्मदार न ठहराया जाये''। अर्थात् मुख्यमन्त्री स्वयं ही मान रहे हैं कि सरकार वह नहीं अलगाववादियों के हाथ में है और वह तो निस्सहाय व असहाय है।

जिस दिन कोई सरकार कानून का सम्मान करने वाले नागरिकों को संरक्षण और कानून भंग करने वालों को सज़ा दिलाने में अक्षम हो जायेगी उस दिन उस देश/प्रदेश में प्रजातन्त्र का जनाज़ा निकल जायेगा। इस 26 जनवरी को यह स्पष्ट हो ही जायेगा। ■

(लेखक भाजपा साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं)

भारी मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार से आम आदमी दुखी : शाहनवाज हुसैन

[kkद्य तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि से संप्रग सरकार की घोर असफलता एवं आम आदमी की हालत के प्रति उसकी पूर्णतया लापरवाही और उपेक्षा का पता चलता है। गत एक वर्ष से अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार दिये गए आश्वासनों के बावजूद आम आदमी को, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतू किसी ठोस कार्यवाही के बजाय कुछ घोषणाएं तथा खोखले आश्वासन ही मिले। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन खोखले और अर्थहीन साबित हुए क्योंकि बाद में इनपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि संप्रग वायदा न निभाने वाला गठबंधन बन गया है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा 17 जनवरी, 2011 को दिया गया प्रेस वक्तव्य

वस्तुतः सभी खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर वृद्धि का कारण संप्रग–कांग्रेस शासन की गलत आर्थिक नीतियां हैं। यह बडे दुःख की बात है कि स्वयं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई अनेक उच्च स्तरीय बैठकों के बाद भी जो परिणाम निकला वह एक महीने में पेट्रोलियम मूल्य में एक बार फिर से वृद्धि किया जाना तथा मुद्रा–स्फीति को कम करने के लिए किसी कार्ययोजना का न बनाया जाना ही है।

ऐसा प्रतीत होता है कि संप्रग सरकार ने आम आदमी को हो रही दुःख तकलीफों के प्रति आंखें बन्द कर ली हैं। ऐसा लगता है कि सरकार इच्छाशक्ति और कार्य–शक्तिविहीन हो गई और वह मंहगाई को रोकने के लिये कोई रणनीति बनाने में असफल रही है। थोक मूल्य सूचकांक में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो गई है। गत 1 महीने में अनेक वस्तुओं के मूल्यों में 100 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है। गेहूं, दालों, चाय, काफी, चीनी, मसालों और सामिश उत्पादों जैसी आठ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में गत 1 वर्ष में औसतन 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दालों, काफी, चाय और मसालों के मूल्यों में 24 से 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गेहूं, दूध, अंडों, मछली,मीट और चीनी के मूल्यों में 8 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। खाद्य वस्तुओं के मूल्य 18.32 प्रतिशत बढ़े हैं।

फिर भी, सरकार अपनी गम्भीर निंद्रा से नहीं जागी है और केवल ऊपरी हमदर्दी दिखा रही है। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में हाल ही में वृद्धि करके संप्रग सरकार ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है और इससे मुद्रास्फीति और बढ़ गई है।

महंगाई के मुददे पर संप्रग–कांग्रेस शासन ने पूर्णतया निष्क्रियता दिखाई है और वह कई भाषाओं मे बात कर रही है। जहां कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के लिये अपनी जिम्मेदारी को मानने से इन्कार किया है, वहां तृणमूल कांग्रेस ने पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि का यह कहकर विरोध किया है कि इस मुद्दे पर उससे सलाह नहीं की गई थी। एक ओर सुश्री ममता बैनर्जी खुले तौर पर संप्रग सरकार का विरोध करती है, दूसरी ओर वह उसी नाकारा सरकार को समर्थन जारी रखे हुई हैं। श्री राहुल गांधी ने तो इसके लिये गठबंधन राजनीति को दोष दिया है। भाजपा जानना चाहती है कि गठबंधन की संप्रग सरकार की इस निष्क्रियता के कारण आम आदमी क्यों नुकसान उठाए?

भाजपा की यह राय है कि संप्रग–कांग्रेस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण मूल्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के लिये सरकार स्वयं उत्तरदायी है और वह सरकार से आग्रह करती है कि वह मंहगाई को रोकने के लिये तुरन्त एक कार्य योजना की घोषणा करे।

ऐसा प्रतीत होता है कि संप्रग सरकार मंहगाई और भ्रष्टाचार के मुददे पर पूर्णतया अल्पमत में है। तथापि, संप्रग सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का विरोध कर रही गठबंधन पार्टियों को मंहगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर स्पष्ट रवैया अपनाना चाहिए और केवल लोगों को दिखाने के लिये इसका विरोध करने के बजाय उन्हें सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए न कि चुनावी लाभों के लिये संप्रग में बना रहना चाहिए।

संप्रग सरकार, जो आम आदमी को पेश आ रही समस्याओं का समाधान करने के आश्वासन से सत्ता में आई थी, वह स्वयं आम आदमी के लिये एक समस्या बन गई है। भारी मुद्रास्फीति और व्याप्त भ्रष्टाचार से पिस रहे लोग बहुत ही दुःखी है। उनमें संप्रग सरकार की नीतियों के विरूद्ध भारी रोष है।

हमारे प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री हैं, परन्तु उनकी विशेषज्ञता का कोई लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि वह निरंकुश मुद्रास्फीति से उत्पन्न चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए मार्गोपाय सुझाने के लिये गठित समिति ने भी कुछ कदम उठाने की अनुशंसा की है जिनमें आम आदमी को रिटेल सेक्टर आदि खोले जाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। समिति ने मुद्रास्फीति रोकने के लिये कतिपय ठोस कदम उठाने हेतु कोई सुझाव नहीं दिया है।

भाजपा मांग करती है कि सरकार और प्रधानमंत्री इस मुददे पर विपक्ष को विश्वास में ले और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिये एक स्पष्ट रणनीति बनाये। जमाखोरों और काला–बाजारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार के पास पड़े खाद्यान्नों के सुरक्षित स्टॉक का उपयोग सप्लाई स्थिति सुधारने के लिये किया जाना चाहिए। मूल्य स्थिति पर नियमित रूप से निगरानी रखने और मांग–आपूर्ति परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बाजार में किसी प्रकार की कृत्रिम कमी को रोकने और बाजार में पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये एक विशेष सेल गठित किया जाना चाहिए।

भाजपा की यह राय है कि संप्रग–कांग्रेस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण मूल्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के लिये सरकार स्वयं उत्तरदायी है और वह सरकार से आग्रह करती है कि वह मंहगाई को रोकने के लिये तुरन्त एक कार्य योजना की घोषणा करे। ■

~~~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~~

पृष्ठ 20 का शेष

देख रहे हैं कि उन्होंने आम आदमी के लिए किया क्या है, जिसके बारे में वे हर रोज कसमें खाते नहीं थकते। वह तो देश की ज्वलंत समस्याओं पर मुंह खोलने से भी कतराते हैं। जैसे युवाओं में बेरोजगारी मिटाना और निर्धनता उन्मूलन, काश्मीर समस्या, महंगाई और मुद्रास्फीति जिसके कारण आम आदमी बेहाल हो गया है।

कांग्रेस को राहुल से बड़ी उम्मीदें हैं और उसे उम्मीद है कि वह उन राज्यों में जहां पहले बुरी तरह हारी है, वहां फिर से जीत पाएगी?

उन्हें इस प्रकार की बड़ी उम्मीदें पालने का पूरा हक है। जब से वे कांग्रेस के महासचिव बने हैं तब से अब तक उनकी उपलब्धियां लोग स्वयं देख सकते हैं। ये बेहद निराशाजनक हैं। युवाओं में सुधार लाने के उनके सारे नए से नए उपाए धरे के धरे रह गए हैं। एनएसयूआई ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर छात्र चुनावों में मात खाई है। कांग्रेस को बिहार विधान सभा में बुरी तरह मात खानी पड़ी है जहां उनके विधायकों की संख्या घट कर मात्र चार तक रह गई है। छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक एवं अन्य जगहों पर भी कांग्रेस बुरी तरह पिटी है।

आपके पास युवाओं की मदद के लिए क्या योजना है?

मैं युवाओं को देश के सामने फैली ज्वलंत समस्याओं पर अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए मंच तैयार करना चाहता हूं, जहां वे इन समस्याओं के समाधान के लिए अपने सुझाव दे सकें। और मेरा विचार है कि केवल भाजपा और भाजयुमो ही एक ऐसा स्वस्थ वातावरण और अवसर प्रदान कर सकती है, जहां वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा, बौद्धिकता और कठिन परिश्रम के आधार पर ऊंचे उठ सकते हैं। ■
~~~~~~~~~~

शास्त्रीय संगीत सम्राट पं. भीमसेन जोशी नहीं रहे

हिदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी का 24 जनवरी 2011 को पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया। शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले पं. जोशी की आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। वे ख्याल गायकी और भजन के लिए काफी मशहूर थे। उनका जन्म वर्ष 1922 में कर्नाटक में हुआ था। पंडित जोशी को 2008 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का शोक संदेश

महान शास्त्रीय गायक और 'भारत रत्न' पंडित भीमसेन जोशी के निधन का दुःखद समाचार मिला। उसके निधन से हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक युग का अवसान हो गया।

पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायकी और भजन के सम्राट थे। वे एक महान संगीत साधक थे। उनके सुर से मानों भारत ही बोलता था। उनके सुरों ने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध किया। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं हैं मगर उनके सुर हमारी अमूल्य विरासत बन गए हैं।

पंडित जोशी ने अपनी विशिष्ट शैली से किराना घराने को समृद्ध भी किया और भारतीय संगीत को नए–नए शिखरों पर पहुंचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों व सहयोगियों को यह असीम दुःख सहने की शक्ति दे।

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी का शोक संदेश

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने भारत रत्न पंडित जोशी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री जोशी असाधारण प्रतिभाशाली शास्त्रीय गायक थे।

उनका जन्म गडग जिला, कर्नाटक में हुआ था और उन्होंने शास्त्रीय तथा जनसाधारण दोनों प्रकार के लोगों को अपने गायन से जबरदस्त प्रभावित किया।

24 जनवरी को श्री जोशी के निधन से भारतीय संगीत के जगत में एक अपूरणीय क्षति हुई है।

भाजपा अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी का शोक संदेश

सुविख्यात सुरसम्राट, 'भारत रत्न' पं. भीमसेन जोशीजी के निधन का समाचार आघात पहुंचाने वाला है।

दशकों से अपने मधुर एवं ओजस्वी, स्वर से सभी को मंत्रमुग्ध कर देना वाला स्वर अब कभी सुनाई नहीं देगा, यह विश्वास नहीं होता। उनके यूं चले जाने से लगता है कि संगीत के इंद्रधनुषी रंगों में से एक लुप्त हो गया है।

किराना घराना के पं. भीमसेन जीशीजी ने 'मेरा' और 'तुम्हारा' सुरों को मिलाकर 'हमारा सुर' बनाया था। आज यही स्वर शांत हो गया है। उनके निधन से न केवल संगीत की दुनिया और उनके प्रशंसकों का चहेता चला गया है अपितु भारत का रत्न भी हमसे दूर चला गया है।

मैं उन के प्रति अपनी विन्रम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही उनके परिजनों तथा प्रशंसकों को यह असहनीय दुःख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं।■

मनमोहन सरकार भारत के इतिहास की भ्रष्टतम सरकार : अरुण जेटली

loknnkrk }kjk

Hkk जपा के वरिष्ठ नेता, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री अरुण जेटली ने कहा है कि मनमोहन सरकार भारत के इतिहास की भ्रष्टतम सरकार है। यह सरकार पूरी तरह से विफल सरकार है। कोई भी परिस्थिति इसके नियंत्रण में नहीं है। जनता मनमोहन सरकार के कुकृत्यों से आजिज आ चुकी है। इस सरकार से देश को छुटकारा दिलाने के लिए भाजपा को आरपार की लड़ाई लड़नी है। यह युद्ध हमें हर हाल में जीतना है। इसके लिए देश के आम आदमी तक तर्क और तथ्यों सहित घोटालों तथा असफलताओं की हर गाथा हमें पहुंचानी होगी तभी देश को कांग्रेसी कुराज से छुटकारा मिल पायेगा।

श्री जेटली 11 जनवरी को भाजपा दिल्ली प्रदेश मुख्यालय में आहूत कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। सम्मेलन 2 जी स्पेक्ट्रम और बोफोर्स भ्रष्टाचार मुद्दे पर जनजागरण अभियान प्रारम्भ करने हेतु बुलाया गया था। इसको राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा, राष्ट्रीय मंत्री सुश्री आरती मेहरा ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने की।

श्री जेटली ने कहा कि हद तो तब पार हो गई जब केन्द्रीय संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने पत्रकार वार्ता आयोजित करके 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि 2 जी स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकारी खजाने

को कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। यह तो चोरी और सीनाजोरी जैसी स्थिति है। यदि 2 जी स्पेक्ट्रम नीलामी में कोई घोटाला नहीं हुआ है तो प्रधानमंत्री ने ए राजा को क्यों हटाया ? सीबीआई 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में क्यों कर रहा है ? उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कभी भी किसी संवैधानिक संस्था में भरोसा था ही नहीं। कांग्रेस जब भी सत्ता में आई, उसने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर ही किया है। वर्ष 2010 को घोटालों का वर्ष बताते हुए श्री जेटली ने कहा कि वर्ष 2011 घोटालों को छुपाने का वर्ष के रूप में कांग्रेस मना रही है। सच को छुपाया नहीं जा सकता है। सच तो सच ही होता है। वह एक दिन सामने आता जरूर है, जैसा कि बोफोर्स दलाली प्रकरण को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने देश और विश्व के सामने लाकर रख दिया है। श्रीमती सोनिया गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि बोफोर्स दलाली का धन कांग्रेस के प्रथम परिवार की दहलीज तक गया है। श्री जेटली ने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी देश को बताएं कि क्या ओत्तावियो क्वात्रोची उनसे दिन में चार–चार बार मिला है या नहीं ? नरसिंहराव की सरकार ने क्वात्रोची को देश से बाहर भागने दिया। राजीव गांधी सरकार ने लंदन स्थित उसके खाते को खुलवाया और पैसा निकालने का मौका क्वात्रोची को दिया। मनमोहन सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में शपथपत्र दाखिल कर कहा कि बोफोर्स मामले को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अब यह साफ हो गया है कि बोफोर्स मामले में राजीव गांधी सरकार ने दलाली दी थी। दलाली की रकम सोनिया के नजदीकी क्वात्रोची तथा दो अन्य व्यक्तियों को चुकाई गई थी।

उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सामाजिक योजनाओं का दो तिहाई धन वास्तविक हकदार तक नहीं पहुंचता है। राष्ट्रमंडल खेलों के नाम पर 70 हजार करोड़ रूपए का घोटाला किया गया। देश की वित्तीय स्थिति डांवाडोल है। रिजर्व बैंक ने एक साल में छह बार ब्याज की दरें बढ़ाई हैं फिर भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है।

कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने श्री अरूण जेटली तथा आये हुये अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि घोटालों की सरताज यूपीए–2 सरकार को हटाये बगैर देश का भविष्य अंधकारमय है। मनमोहन सरकार के हाथ से स्थितियां निकल चुकी हैं। हर मामले में यह एक विफल सरकार है। इस सरकार को अपदस्थ करके पुनः देश में राजग की सरकार कायम करना ही भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री श्री आशीष सूद ने किया। ■

मध्यप्रदेश

कार्यकर्ता पार्टी का चेहरा है, कर्मठता, सेवा भावना, समन्वय की नई मिसाल कायम करें : प्रभात झा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री प्रभात झा ने संभागीय पदाधिकारियों व पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मासांत तक पार्टी के नये दस लाख सदस्य पार्टी से जुड़ जायेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने रतलाम, होशंगाबाद में संपन्न प्रदेश कार्यसमिति की बैठकों में संगठन में शुचिता, सादगी, आडंबर विहीन आचरण के बारे में जो निर्णय लिये है कार्यकर्ताओं ने उन पर पूरे मनोयोग से अमल किया है। रीवा में संपन्न महिला मोर्चा की प्रदेश की बैठक में सादगी का नया कीर्तिमान बना है। पार्टी के कार्यकर्ता ही पार्टी का चेहरा है। उनकी सेवा भावना और सादगी, जनता के प्रति संवेदना ने उन्हें जनता के अधिक निकट पहुंचाया है। उसी का नतीजा है कि हाल में संपन्न नगरीय निकायों के चुनाव में मतदाताओं ने भाजपा को कांग्रेस की परंपरागत सीटें भी सौंप दी है। भाजपा को शानदार जीत हासिल हुई है।

प्रदेश में संपन्न कार्यकर्ता गौरव दिवस के सफल आयोजन का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता और कर्मठता को जाता है।

श्री प्रभात झा ने कहा कि देश आतंकवाद और अलगाववाद में झुलस रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने जो गलती की उसका खामियाजा आज तक देश को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि देश की अखण्डता के लिये आजादी के बाद यदि किसी दल ने कुर्बानी दी है तो वह जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ही रही है। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने देश की अखण्डता के लिये जीवन की आहूति दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राष्ट्रीय एकता यात्रा का आयोजन कर देश में नई चेतना का संचार किया है। देश के युवकों में अखण्डता की रक्षा में जूझने का साहस सशक्त हुआ है। अलगाववादियों के पेट में मरोड़ हुई है।

श्री प्रभात झा ने ग्वालियर चंबल संभाग के जिला पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे आगामी सप्ताह के अंत तक जिलों का समग्र रूप से गठन कर लें। मोर्चा और प्रकोष्ठों का मंडल स्तर तक विस्तार करे। आपने कहा कि हमें अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए। जिला कार्यालय को सेवा का केन्द्र बनाएं। कार्यालय के प्रति देवालय की तरह आस्था पैदा करें।

श्री प्रभात झा ने कहा कि जल्दी ही कार्यालय मंत्रियों, महामंत्रियों और पदाधिकारियों के वर्ग आयोजित किये जायेंगे। सरकार और संगठन में समन्वय बनाकर जो सफलता अर्जित की है उसे आगे बढाएं। कार्यकर्ताओं की सक्रियता और कर्मठता के बल पर भाजपा प्रदेश में दोबारा सत्ता में आयी है। श्री मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाना है। लोकसभा चुनाव में भारी विजय प्राप्त कर दिल्ली में सरकार बनाने का मार्ग मध्यप्रदेश से प्रशस्त करना है।

उत्तराखंड

२०११ में पूरे करेंगे नये संकल्प : निशंक

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए देश व प्रदेश के उज्ज्वल, सुखमय भविष्य, समृद्धि एवं निरंतर प्रगति की कामना की है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 2010 आम आदमी की बेहतरी और खुशहाली के लिए जाना जाएगा। इस वर्ष शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं 2011 में क्रियान्वित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2010 में सरकार ने अनेक जनहित और कल्याणकारी कदम उठाये हैं। सरकार ने आम आदमी तक सस्ता राशन पहुंचाने का बीड़ा उठाया और

गुजरात

'वाइब्रेंट गुजरात' एक प्रेरणा : नितिन गडकरी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की प्रशंसा करते हुए इसे एक अद्‌भुत उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह पार्टी की अन्य सरकारों को प्रोत्साहित और प्रेरित करेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में श्री गडकरी ने कहा कि पार्टी को इस बात का गर्व है कि उसके द्वारा शासित एक राज्य 'देश भर के लिए विकास का एक आदर्श बना है।'

श्री गडकरी ने कहा, 'गुजरात सरकार द्वारा रिकार्ड निवेश को आकर्षित करना निवेशक समुदाय के भरोसे का एक प्रमाण है जिसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लगातार दिखाया है।'

उन्होंने कहा कि गुजरात के ग्रामीण और शहरी विकास में एक सही संतुलन कायम किया गया है। इससे यहां जीवन 'अत्यधिक रहने योग्य' और राज्य 'निवेश का आकर्षण' बना है।

श्री गडकरी ने कहा, 'उन राज्यों में जहां हमारी सरकार है वहां हम अच्छे प्रशासन का उदाहरण पेश करने पर जोर दे रहे हैं। हमारा मानना है कि 'वाइब्रेंट गुजरात' एक शानदार सफलता है जो अन्य सरकारों को प्रोत्साहित और पार्टी को प्रेरित करेगा।' मोदी के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए गडकरी ने कहा कि राज्य आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और सफलतापूर्वक रिकार्ड निवेश आकर्षित कर रहा है। उल्लेखनीय है कि पांचवां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल निवेश सम्मेलन 2011 का गुरुवार को गांधीनगर में समापन हुआ।

समापन के मौके पर श्री मोदी ने कहा कि सम्मेलन में 20,83,000 रुपये (462 अरब डॉलर) के निवेश वाले 7936 सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए। इनके अमल में आने पर राज्य में 52 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन की उम्मीद है। ■

➔

इसकी दरों में अभूतपूर्व कमी की। विभागों में रिक्त पदों पर प्रोन्नति के लिए कार्मिकों को सेवा अवधि में छूट, विभिन्न विभागों की नियमावली में संशोधन के फैसले लेकर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये। स्टाफिंग पैटर्न लागू करने से साथ ही वर्ष 2000 तक कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मी और वर्कचार्ज कर्मियों को नियमित करने का फैसला भी लिया। रोजगार के अवसरों में 21 हजार नौकरियों के द्वार खोले गये और उत्तार प्रदेश से आने वाले 4 हजार पुलिस कर्मियों के स्थान पर स्थानीय नौजवानों की भर्ती का निर्णय भी लिया। यह वर्ष युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रहा है।

उन्होंने कहा कि 2010 में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की विभिन्न स्तरों पर प्रशंसा की गई। केंद्रीय योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार घरेलू पर्यटकों की संख्या की दृष्टि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर और देश के समस्त राज्यों में सातवें स्थान पर रहा है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ठोस कार्य हुए जिसे राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग द्वारा सराहा गया और देश में उत्तराखंड को प्रथम स्थान पर रखा। कुंभ मेले का सफल आयोजन और आपदा मानकों में भारी वृद्धि भी इस वर्ष की उपलब्धि है। ■

महाराष्ट्र

भाजपा महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मोर्चा का ''मुस्लिम महिला विकास सम्मेलन''

मुस्लिम महिलाएं सक्षम परन्तु अवसर नहीं मिलता : नजमा हेपतुल्ला

Hkkरतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से मुंबई में 15 जनवरी को आयोजित ''मुस्लिम महिला विकास सम्मेलन'' का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, इसमें 2500 से अधिक मुस्लिम महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को घर बैठे रोजगार के अवसर प्रदान करना था। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से मोहतरमा नजमा हेपतुल्ला उपाध्यक्ष भाजपा, जनाब तनवीर अहमद अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, हाजी हैदर आजम अध्यक्ष भाजपा महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मोर्चा, जनाब राज पुरोहित अध्यक्ष भाजपा मुंबई, जनाब अतुल शाह प्रवक्ता भाजपा महाराष्ट्र, मोहतरमा शायना एनसी उपाध्यक्ष भाजपा मुंबई, मोहतरमा शैलेजा गिरकर उपमहापौर मुंबई, मोहतरमा विंदा कीर्तिकर अध्यक्ष भाजपा मुंबई महिलाओं मोर्चा आदि उपस्थित थे। सम्मेलन की अध्यक्षता मोहतरमा स्मृति ईरानी अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा ने की। इस सम्मेलन में बोलते हुए सभी वक्ताओं ने इस सफल सम्मेलन के आयोजन पर हाजी हैदर आजम को मुबारकवाद दी। जनाब राज पुरोहित ने कहा कि हमें विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं उपस्थित होंगी परन्तु लोगों में जागरूकता लाकर यहां तक लाने का काम हैदर आजम ने बहुत अच्छा नेतृत्व निभाया। जनाब अतुल शाह ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को अब आगे बढ़कर अपना विकास व अपनी आर्थिक उन्नति के खड़े होना चाहिए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनाब तनवीर अहमद ने कहा कि अब मुसलमानों ने दोस्त दुश्मन का अंतर समझ लिया। हाजी हैदर आजम ने अपने संबोधन में आई हुई सभी महिलाओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम समाज आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा है जिसकी उन्नति जरूरी है। सभा को मोहतरमा शायना एनसी विंदा कीर्तिकर, शैलेजा गिरकर आदि ने भी संबोधित किया। मोहतरमा नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के विकास के लिए मैं घर–घर जाउंगी व सभी को जागरूक करेंगी। उन्होंने कहा कि आज मैं जिस स्थान पर हूं उसमें मेरे पति व मेरे भाइयों का पूरा सहयोग रहा इसलिए सभी को चाहिए को महिलाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। मोहतरमा स्मृति ईरानी ने संबोधित करते हुए कहा कि मुझे बहुत दुःख होता है जब हमारी मुस्लिम बहनें आज के इस महंगाई के दौर में बड़ी कठिनाईयों में अपना परिवार चलाती है।

उन्होंने कहा कि आज देश के विकास के लिए उनका विकास बहुत जरूरी है। इसीलिए आज के इस सम्मेलन के

माध्यम से उन बहनों को घर बैठे रोजगार के उपाय व योजना कि जानकारी देना व उनकी मदद करना बहुत जरूरी है इस विषय पर मैं हैदर आजम व नजमा हेपतुल्ला के साथ गंभीरता से काम करूंगी। उन्होंने स्वस्थ देश के लिए स्वस्थ नारी का होना जरूरी बताया व चिकित्सा के क्षेत्र में काम को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने नारी शक्ति को बढ़ावा देने के उपायों पर भी चर्चा की। इस सम्मेलन का संचालन मोहतरमा महजबीं शेख व मोहतरमा इशरत सय्यद ने किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने जोश–खरोश से भाग लिया।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

उत्तर प्रदेश

विकास व स्वच्छ प्रशासन ही एजेंडा : तोमर

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विकास, रोजगार एवं बसपा शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर सुशासन के वादे के साथ ही भाजपा जनता के बीच जाएगी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में आगामी सरकार भाजपा की ही बनेगी। बुलंदशहर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ वर्षों में पार्टी कुछ कमजोर हुई है। इसकी वजह पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में जाति–पांत की राजनीति का हावी होना रहा। भाजपा अवसरवाद या जातिवादी भेड़चाल में शामिल नहीं हुई। अब संगठन को फिर से मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। गांव चलो अभियान के तहत प्रदेश के 52 हजार ग्राम सभाओं में 5200 टोलियां एक माह तक प्रवास करेंगी। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी बिहार विधानसभा चुनाव की तरह विकास एवं स्वच्छ प्रशासन की बातें होंगी। बिहार की सफलता उत्तर प्रदेश में भी दोहराई जाएगी। ■

उपाला में केरल रक्षा पद यात्रा

गत 16 जनवरी को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कसारगोड के उपाला शहर की उत्तरी सीमा पर केरल रक्षा पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मुरलीधरन 'मार्च' के संयोजक को पार्टी ध्वज सौंपकर रवाना किया।

इस मार्च का आयोजन अप्रैल–मई में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा का खाता खोलने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, यात्रा 26 फरवरी को तिरुवनंतपुरम में समाप्त होगी। यह राज्य के 14 जिलों में 12 जिलों के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से गुजरेगी। वायानाड़ और इदिक्की जिलों के कार्यकर्ता और समर्थक समीपवर्ती जिलों में इस मार्च का स्वागत करेंगे।

यात्रा केरल की एलडीएफ सरकार और केन्द्र में यूपीए सरकार इन दोनों की जन–विरोधी नीतियों के खिलाफ अभियान होगा क्योंकि इन दोनों ही सरकारों के अन्तर्गत भयंकर भ्रष्टाचार और आतंकवाद का खतरा विकराल रूप धारण किए हुए हैं।

भाजपा संसदीय पार्टी के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, तथा अन्य राष्ट्रीय नेतागण 26 फरवरी को यात्रा के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने मार्च को हरी झण्डी दिखाते हुए कहा कि केरल की सरकारों ने राज्य की औद्योगिक आवश्यकताओं को नजरअन्दाज किया है। इस समय, केरल की अर्थव्यवस्था राज्य के बाहर और खाड़ी देशों से प्राप्त होने वाले मनी आर्डरों पर टिकी हुई है।

श्री गडकरी ने कहा कि इस समय केरल को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बढ़ने की गहन आवश्यकता है, जिसके लिए केरल को गुजरात के मॉडल को अपनाना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि केरल में अधिस्थापित सभी सरकारों ने राज्य के कृषि क्षेत्र की भी उपेक्षा की है। उन्होंने पुलुमेडु की भयंकर त्रासदी का उदाहरण दिया जिसमें 102 सबरीमाला पीड़ितों की मृत्यु हो गई थी। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि केरल की सरकारों ने तीर्थ यात्रियों की बुनियादी–सुविधाएं तक प्रदान नहीं की हैं। उन्होंने उक्त त्रासदी के प्रसंग में दक्षिणी राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने पर भी बल दिया है। ■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~